कमल संदेश
ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिवशक्ति बक्सी

संपादक मंडल

सत्यपाल
संजीव कुमार सिन्हा

कला संपादक

धर्मेन्द्र कौशल
विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-
त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

InL;rk : +91(11) 23005798
Qku (dk-) : +91(11) 23381428
QDI : +91(11) 23387887

पता : डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003

ई–मेल

kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक – प्रभात झा

विषय–सूची

मुम्बई में आयोजित दो दिवसीय भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का दीप प्रज्जवलन कर शुभारंभ करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी, भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी, लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज, राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली एवं मुम्बई भाजपा अध्यक्ष श्री राज पुरोहित।

अध्यक्षीय भाषण..... 7

सूखे की स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव..... 14

कृषि संबंधी प्रस्ताव..... 16

राजनैतिक प्रस्ताव..... 22

आर्थिक प्रस्ताव..... 26

जम्मू और काश्मीर पर वार्ताकारों की रिपोर्ट पर वक्तव्य..... 30

बोध कथा

न्याय और धर्म

एक न्यायाधीश थे। न्याय के साथ धर्म में भी उनकी गहरी आस्था थी। वह नियमित पूजा–पाठ करते थे और प्रवचनों में भी शामिल होते थे। एक बार एक चोर उनके सामने लाया गया। वह मोहल्लों में छोटी–मोटी चोरी किया करता था। चोर न्यायाधीश महोदय के धर्मपरायण होने की बात को बखूबी जानता था। उसने थोड़ी ही देर में अपना अपराध स्वीकार कर लिया। फैसला सुनाने से पहले न्यायाधीश ने चोर से पूछा– तुम्हें अपने पक्ष में कुछ कहना है तो निःसंकोच कह सकते हो।

इस पर चोर बोला– श्रीमान, आज आपके सामने खड़ा होने में मुझे आनंद आ रहा है। मैंने सुना है कि आप बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं। मुझे सिर्फ यही कहना है कि मैंने अपने लिए चोरी नहीं की। भगवान ने मुझे इसके लिए प्रेरित किया। उनकी इच्छा से मेरे हाथों चोरी हुई। इसलिए मुझे दोषी न ठहराया जाए। यह सुनते ही वहां उपस्थित लोग सन्न रह गए। उनमें से कुछ ने कहा कि यह चोर महा धूर्त है इसने न्यायाधीश महोदय को अपने दांव में फंसा लिया है।

लोगों को लगने लगा कि कहीं यह साफ छूट न जाए। लेकिन न्यायाधीश महोदय ने जो कुछ भी कहा उसने सबको चकित कर दिया। वे चोर से बोले– तुम्हारा कहना मुझे पूरी तरह मान्य है। जिस भगवान ने तुम्हें चोरी करने की प्रेरणा दी है वही भगवान अब मुझे तुम्हें सजा देने की प्रेरणा दे रहा है। तुम्हें एक साल की कैद की सजा दी जाती है। इस तरह एक बार फिर न्यायाधीश ने अपने फैसले से लोगों का दिल जीत लिया।

संकलनः त्रिलोक चंद जैन
साभारः नवभारत टाईम्स

व्यंग्य चित्र

हमें लिखें...

सम्पादक के नाम पत्र

कमल संदेश

सादर आमंत्रित

आपकी राय एवं विचार

सम्पादक,
कमल संदेश
डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी–66
सुब्रह्मण्य भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003
ई-मेलः
kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रिय पाठकगण

कमल संदेश (पाक्षिक) का अंक आपको नियमित मिल रहा होगा। यदि किन्हीं कारणवश आपको कोई अंक प्राप्त न हो रहा हो तो आप अपने प्रदेश कार्यालय को या हमें अवश्य सूचित करें।

-सम्पादक

विशेष सम्पादकीय

मजबूत संगठन निर्माण के लिए एकजुट हो कमर कस मैदान में उतरें

पिछले दिनों भाजपा शासित राज्य कर्नाटक, गुजरात एवं राजस्थान भाजपा में जो कुछ हुआ उससे आम नागरिकों को काफी तकलीफ हुई। तकलीफ उनको भी हुई जो भाजपा के 'कार्यकर्ता' हैं और 'समर्थक'। घटना अच्छी होती तो तकलीफ नहीं होती। घटना दुःखद और भाजपा की प्रकृति के विरुद्ध होने के कारण सभी को तकलीफ हुई। खुश वे भी नहीं हुए होंगे, जिनके कारण देश और दल दुःखी हुआ। मूल में भाजपा की प्रकृति इस तरह की नहीं है। भाजपा नेता में अपने वजूद के लिए लड़ाई लड़ने का स्वभाव नहीं रहा। यहां तो लोग वर्षों से पार्टी की वजूद के लिए लड़ते रहे। कक्षा का विद्यार्थी बिगड़े तो समझ में आता है पर यहां तो शिक्षक और प्रधानाचार्य पटरी से उतरने की तैयारी कर रहे हैं। पार्टी पटरी है और उस पर संगठन की रेल चलती है। बहुत यात्री आए और बहुत यात्री गए। रेल के डिब्बे में बैठे हैं तो कभी न कभी उतरना होगा और रेल है तो यात्री नए भी आएंगे। पुराने भी रहेंगे। कुछ चढ़ेंगे, कुछ उतरेंगे। कभी–कभी अधिक भीड़ होने से कुछ आवश्यक यात्री को भी स्टेशन पर ही रुक जाना पड़ता है। पर वह यात्री दूसरी रेल का इंतजार करता है। वह जल्दबाजी में न किसी यात्री को घसीटता है, न रेल पर पथराव करता है और न पटरी उखाड़ता है। फिर अपने हाथ से बिछाई पटरी को, अपने हाथ से बनाए रेल के डिब्बों को अगर रोज सफर करने वाले यात्री तोड़ने लगेंगे तो हम अपनी लक्षित यात्रा पर कैसे पहुंच पाएंगे? पार्टी व्यवस्थाओं से चलती है। व्यवस्थाएं पार्टी में कार्यरत लोगों द्वारा कायम रखी जाती हैं। पार्टी किसी एक के सहयोग से नहीं सभी के सहयोग से चलती है। 'सिर्फ मेरी ही चलेगी, मेरी नहीं तो किसी की नहीं चलेगी', की तर्ज पर न संगठन चलता है, न समाज और न ही परिवार।

परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जब हम बने होंगे तब भी कोई हटा होगा। जब हम हटेंगे तब भी कोई बनेगा। धरा पर कौन हमेशा के लिए आया है। 'जो आया है वह जाएगा', के अकाट्य सत्य को जानने के बाद भी लोग शृंगारित होने के पश्चात् निर्मात्री और जन्मात्री को ही क्यों कोसने लगते हैं? संगठन मां है। वह अपनी वात्सल्यता से हमारा निर्माण करती है। वर्षों लग जाते हैं किसी कार्यकर्ता के निर्माण में। विध्वंस क्षणिक होता है। निर्माण वर्षों का समय लेता है। निर्माण में एक नहीं अनेक की भूमिका होती है पर विध्वंस के लिए तो कोई एक ही काफी होता है।

हमें विचार करना होगा कि कहीं हमारी निर्माण पद्धति में कोई कमी तो नहीं आ गई। 'नींव से कलश तक' के निर्माण में कहीं हम ठहर और सहम तो नहीं गए। आखिर उस वजह को तो ढूंढना ही होगा जो कलश के बाद कोलाहल की ओर बढ़ने लगती है। आखिर वह विचार क्यों नहीं करता कि उसे कलश किसने बनाया। क्या उसे कलश बनने में उसकी अकेले की भूमिका थी? क्या वह कलश नींव को हिलाने के लिए बना था? क्या कलश की प्रकृति यही होती है कि वह जिस नींव पर खड़ा रहे, उसी को हिलाता रहे। विचार तो इस पर भी करना होगा कि आखिर यह परिस्थिति क्यों बनती है? हम सभी जानते हैं कि संगठन से सत्ता का निर्माण होता है न कि सत्ता से संगठन का। विश्व का राजनीतिक इतिहास जब आंखों से गुजरता है तो लगता है कि सबने एक स्वर में कहा है ''संगठन सर्वोपरि होता है।'' जब राजा हुआ करते थे तब भी

विशेष सम्पादकीय

वे धर्माचार्य की बात मानते थे। आज जब लोकतंत्र हैं तो धर्माचार्य की भूमिका संगठन की होती है। ऊंचाई पर हम जाते हैं तो हमारी समझ की ऊंचाई भी बढ़नी चाहिए। पर अक्सर देखा गया है कि अधिक ऊंचाई पर जाने पर आदमी यह जानते हुए कि उसे एक न एक दिन नीचे आना होगा, बावजूद उसके वह नीचे वालों पर आंखें तरेरता है। जरूरत से ज्यादा जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो व्यक्ति के बिगड़ने की संभावना का द्वार हम स्वतः खोल देते हैं। इसी तरह जब हम व्यक्ति की बुराई की इंतहा कर देते हैं तो उसके बाहर जाने का द्वार भी हम ही खोल देते हैं।

संगठन को जमीनी पकड़ बनानी होगी। जब जमीनी पकड़ बनेगी तो जमीन और आसमान के बीच समन्वय रहेगा। आसमान इसलिए टिका है कि उसे यह पता है कि पृथ्वी गोल है और वह सदैव घूमती रहती है। जहां में कभी जो 'जमीन' होता है वह कभी 'आसमान' हो सकता है और जो आसमान है वह कभी जमीन पर आ सकता है। हमको ना अपनों से और ना ही विरोधियों से लड़ना है। हम तो विचार की लड़ाई लड़ते हैं और यह सोचकर लड़ते हैं कि जो आज हमारा नहीं वह आनेवाले दिनों में हमारा हो जाएगा। हमें हमारे लोकव्यवहार पर भरोसा रखना चाहिए। हमारा लोक व्यवहार ही संगठन को विस्तार में कारगर साबित होगा। सोना तपता है, गलता है, तब किसी का शृंगार बनता है। अगर वह यह ठान ले कि मैं न तपूंगा, न गलूंगा, तो भला कौन उसे शृंगार मानेगा? सोना का ढेला गले में कोई नहीं लटकाता। लोग आभूषण पहनते हैं। अटलजी, आडवाणी जी और डॉ. जोशी जी भारतीय राजनीति के क्षितिज पर इसलिए वर्षों से चमक रहे हैं कि इन्होंने सदैव संगठन को सर्वोपरि माना है। अपने को भाजपा के भीतर रखा, बावजूद इसके कि उनका कद बहुत बड़ा है पर उन्होंने अपने कद को पार्टी के कद से ऊंचा नहीं बनाया। यही कारण है कि वह पद पर रहें या न रहें, उनका राजनीतिक कद दल में इतना बड़ा है कि इन्हें सभी नमन करते हैं। नमन देह को नहीं, समर्पण को किया जाता है। समर्पण सहज होता है प्रायोजित नहीं। हम जो आज हैं वो कल नहीं रहेंगे। जो कल होंगे वो परसों नहीं रहेंगे। एक समय ऐसा भी आएगा जब हम कुछ नहीं रहेंगे, पर क्या हम वैचारिक नाभि के संबंधों को भूल जाएंगे?

पिछले दिनों मध्यप्रदेश भाजपा कार्यालय में पूर्व सांसदों व पूर्व विधायकों की बैठक हुई। उस बैठक के समापन समारोह में 87 वर्षीय ज्येष्ठ और श्रेष्ठ नेता श्री सुंदरलाल पटवा ने कहा कि हम जितने लोग यहां बैठे हैं वे सभी पार्टी के कारण जाने जाते हैं। हम पर पार्टी का बहुत बड़ा अहसान है। हम जब तक जीवित हैं, हमें जो पार्टी ने समाज में महत्व दिया है उसके अहसान को नहीं भूलना चाहिए और जीवनपर्यन्त कार्य करके इस कर्जे से उबरते रहना चाहिए। सच में भारतीय जनता पार्टी वर्तमान राजनीति में देश की एक नई उम्मीद है। सब उसकी ओर देख रहे हैं। ऐसे समय में जिसके पास जो जवाबदारी है उसे अपने–अपने स्थानों पर अहम भूमिका निभानी होगी। तेरा–मेरा का चक्कर या अपने अस्तित्व का चक्कर भूलकर सिर्फ हम सभी को पार्टी के अस्तित्व के लिए एकजुट होकर कमर कसकर मैदान में आना होगा। जिस तरह शाखा में हम मुख्यशिक्षक का आदेश मानते हैं। यह हम नहीं देखते कि उसकी उम्र क्या है? वह हमसे छोटा है या बड़ा? हम यह देखते हैं कि वह शाखा का मुख्य शिक्षक है और शाखा पर उसका आदेश मानना प्रत्येक स्वयंसेवक का कर्त्तव्य है। आज किसके पास क्या दायित्व है, महत्व इस बात का नहीं है। जिसके पास जो दायित्व है हमें उनके दायित्व और व्यवस्था की प्रतिष्ठा तो रखनी ही होगी। ■

कांग्रेस समस्या है भाजपा समाधान है : नितिन गडकरी

भारतीय जनता पार्टी की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक 24 एवं 25 मई 2012 को यशवंत राव चव्हाण केंद्र, मुंबई में सम्पन्न हुई। बैठक के पहले दिन अध्यक्षीय भाषण करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने उपस्थित प्रतिनिधियों के संकल्प को मजबूत करते हुए कहा कि हम अपनी एकता, अनुशासन और समर्पण को हर स्तर पर सुदृढ़ करें। उन्होंने कांग्रेसनीत केन्द्र सरकार पर चौतरफा प्रहार करते हुए कहा कि हमारा देश इस समय ऐसे कठिन दौर से गुजर रहा है, जिसके लिए यूपीए का कुशासन मुख्य रूप से जिम्मेदार है। देश में इस वक्त हालात ऐसे हैं कि लोग कांग्रेस की विदाई देखना चाहते हैं। वो बदलाव चाहते हैं और गंभीरता से एक सही विकल्प की तलाश कर रहे हैं। उन्हें भाजपा से बड़ी आशाएं और उम्मीदें हैं। श्री गडकरी ने कहा कि कांग्रेस ने समस्याएं पैदा की हैं, भाजपा समाधान करेगी। हम यहां सुधी पाठकों की जानकारी के लिए इस भाषण का पूरा पाठ प्रकाशित कर रहे हैं :–

सम्मानित साथियों,

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक मुंबई में कई वर्षों के अंतराल पर हो रही है। मुंबई की इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों की शुरुआत करना है, फिर चाहे वो चुनाव 2014 में हों या उससे पहले।

इन चुनावों में हमें जनादेश मिलता दिखाई दे रहा है। आइए, सिंधुसागर के तट पर बसे मुंबई से हम अपनी विजय यात्रा की तैयारी प्रारंभ करें।

दो दिन पहले ही, 22 मई को कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही यूपीए की सरकार के कार्यकाल के आठ वर्ष पूरे हुए हैं। जब किसान आत्महत्या कर रहे हैं, रुपया गिर रहा है, आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं तब यूपीए ने जश्न मनाकर अपनी असंवेदनशीलता का परिचय दिया है। यह सरकार पहले से ही पंगु और बेअसर हो चुकी है। मुंबई से भाजपा इस भ्रष्ट, घोटालों से घिरी, गरीब विरोधी और निरंतर अलोकप्रिय होती जा रही सरकार को ज़ोरदार और स्पष्ट रूप से यह बताना चाहती है कि: "तुम्हारे दिन अब गिनती के हैं। भारत अब तुम्हारे कुशासन को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वक्त आ गया है कि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की वापसी हो ताकि यूपीए द्वारा फैलाई जा रही अराजकता खत्म की जा सके और हम देश को सही दिशा में आगे ले जा सकें।"

अटलजी, हमारे प्रेरणा के स्रोत

भाजपा के इतिहास में मुंबई का गौरवपूर्ण महत्व है। अप्रैल 1980 में पार्टी की स्थापना के बाद दिसंबर में यहीं श्रद्धेय अटलजी के नेतृत्व में पार्टी का पहला पूर्ण अधिवेशन हुआ था।

हम सभी को यहां श्री अटलजी की अनुपस्थिति खल रही है। हालांकि, उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ हैं। हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने और दीर्घायु की कामना करते हैं।

सत्ता में भाजपा की वापसी आज राष्ट्रीय आवश्यकता बन गयी है। इस कर्तव्य को निभाने में हमें सफल होना ही है। राजनीतिक हालात और लोगों का मन, दोनों ही भाजपा की वापसी का समर्थन कर रहे हैं। बस, हमें इस अवसर को खोना नहीं है।

भारत की वर्तमान आर्थिक बदहाली के लिए 'यूरोज़ोन' नहीं बल्कि 'यूपीए-ज़ोन' जिम्मेदार

भारत के लोग बड़ी आशा और उम्मीद के साथ भाजपा की ओर देख रहे हैं। निस्संदेह, जिस अनुपात में लोगों का कांग्रेस से मोहभंग हो रहा है और उसके प्रति गुस्सा बढ़ता जा रहा है, उसी अनुपात में उनकी भाजपा से उम्मीदें भी बढ़ती जा रही हैं। यूपीए का शासनकाल भ्रष्टाचार, घोटालों, नाकामियों और धोखाधड़ी की शर्मनाक कहानी है।

यूपीए सरकार की धोखाधड़ी का सबसे बडा शिकार है आम आदमी, जो भयंकर और निरंतर बढ़ती महंगाई के बोझ तले दबता और पिसता चला जा रहा है। गरीबों और मध्यमवर्ग की परेशानियां कम करने के बजाय इस सरकार ने पेट्रोल के दाम बढ़ाकर लोगों की कमर तोड़ दी हैं। यह सरकार की असंवेदनशीलता का एक और उदाहरण है।

हमारे अर्थशास्त्री–प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत का रुपया गिरता ही जा रहा है। ये डर बेबुनियाद नहीं है कि जल्दी ही रुपया इतना नीचे चला जाएगा कि एक अमेरिकी डॉलर 60 रुपए का हो जाएगा। जी–तोड़ मेहनत से इकट्ठा किया गया भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भारी दबाव में है। सरकार की गलत नीतियों के कारण भारतीय कारोबारियों को देश के बजाय विदेशों में निवेश करने को मजबूर होना पड़ रहा है।

जैसाकि उम्मीद की जा रही थी, सरकार के प्रवक्ता भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्याओं के लिए बाहरी कारणों को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये सरासर बहानेबाजी है। भारत की समस्याओं की असली जड़ यूरोज़ोन नहीं, बल्कि यूपीए–ज़ोन है। पूरे मामले में सच बस इतना है कि ये सरकार फैसला लेने और नीतियां बनाने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। सक्षम नेतृत्व के अभाव ने हालात को और भी बदतर बना दिया है।

यूपीए सरकार के कुशासन का एक और संकेतक केंद्र और राज्यों के संबंधों में बढ़ता तनाव हैं। कई गैर–कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने ये शिकायत की है कि केंद्र में बैठी कांग्रेस पार्टी के अहंकारी नेतृत्व ने राज्य सरकारों की हालत नगर निकायों जैसी कर दी है। ये बात भाजपा को कतई मंजूर नहीं है। इसके विपरीत भाजपा केंद्र और राज्यों के बीच वैसे ही सद्भावपूर्ण रिश्ते विकसित करना चाहती है जैसा श्री अटल बिहारी वाजपेयीजी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के शासनकाल में थे।

कांग्रेस ने समस्याएं पैदा की हैं : भाजपा समाधान करेगी

भाजपा का मानना है कि भारत की आर्थिक नीतियां, स्थायी विकास, रोजगार सृजन, कृषि, ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दें ताकि यह नीतियां अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्रों, अनुसूचित जाति, जनजातियों और अन्य वंचित वर्गों तथा अल्पसंख्यकों को लाभ पहुंचा सकें।

कांग्रेस से इसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। वह तो केवल राहत के झूठे वायदे करती रही है।

जल, ऊर्जा, खाद्य और पर्यावरण सुरक्षा जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियों से निपटने के लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन – दोनों तरह के उपाय तत्काल करने की भी आवश्यकता है।

आज हमारी यह बैठक महाराष्ट्र में हो रही है, जहां के बड़े हिस्से में सूखा पड़ा हुआ है। यह रोजमर्रा की बात हो गई है। राज्य सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए फिर से पानी के टैंकरों का उपाय किया है। आसानी से यह समझा जा सकता है कि पानी गांवों तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि टैंकरों से पानी 'रिसता' रहता है। इस तरह से भ्रष्ट नेता जनता के पैसे को हड़पते रहते हैं।

'टैंकर के उपाय' को मैं उपमा के रूप में इस्तेमाल कर रहा हूं। इसका कारण यह है कि नरेगा, एनआरएचएम, इंदिरा आवास योजना, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन और इसी तरह की कांग्रेस द्वारा घोषित विकास और कल्याण योजनाओं के साथ ऐसा ही हो रहा है।

मेरा मानना है कि इन सारी बुनियादी समस्याओं का समाधान, सुशासन, विकास के अभिनव प्रयोगों, अंत्योदय द्वारा होगा जो हमारी राष्ट्रवादी विचारधारा का मूल है।

हाल ही में अभी मैं इज़राइल की यात्रा से लौटा हूं। वह बहुत छोटा सा देश है जिसकी आबादी मुंबई की आबादी की आधी से भी कम है। उसके पास पानी और हाइड्रोकार्बन संसाधन भी बहुत कम हैं। उसकी सुरक्षा को अपने पड़ोसियों से लगातार खतरा बना रहता है। और, इसके बावजूद इज़राइल की सरकार और जनता ने समूची आबादी की पानी, ऊर्जा, खाद्यान्न, शिक्षा और स्वास्थ्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भरता वाले उपाय विकसित किए हैं। उन्होंने वाकई इज़राइल को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवीनता के क्षेत्र में अग्रणी बना दिया है।

हमें उसी तरह का राष्ट्रवादी, आत्मनिर्भर, विकासोन्मुखी और नवीनतम रवैया अपनाकर भारत की समस्याओं को हल करने की जरूरत है।

मेरी सभी साथियों से अपील है: हमें समस्याओं की चर्चा के साथ साथ समाधान भी देने होंगे।

जब लोग हमें केंद्र में सरकार बनाने के लिए जनादेश दें तो हमारी प्राथमिकताएं महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरु करने की होगी, जैसे अटलजी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना तथा प्रधानमंत्री ग्राम

सड़क योजना चलायी थी। उसी तर्ज पर भारत के कृषि और ग्रामीण विकास के लिए हमें युद्ध स्तर पर जलसंरक्षण मिशन शुरु करना होगा। संसाधनों के अभाव में राज्य सरकारें सिंचाई जैसी बुनियादी समस्या पर ध्यान नहीं दे पा रही हैं। इसी प्रकार केंद्र एवं राज्य सरकार सिंचाई के लिए मिलकर संसाधन जुटा सकते हैं। मेरा मानना है कि इस एक पहल से ग्रामीण भारत की स्थिति उसी तरह बदल सकती है जैसे सड़क परियोजना से शहरों का कायाकल्प हो रहा हैं।

भारतीय संसद ने अभी हाल ही में 60 वर्ष पूरे किए। इस अवसर पर हमें 'सशक्त संसदीय प्रणाली' बनाने के लिए देश को आह्वान करना चाहिए। न केवल संसद बल्कि राज्य विधानसभाओं और पंचायती राज संस्थाओं को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाने के लिए हमें राष्ट्रीय स्तर पर बहस शुरू करनी चाहिए। हमें चुनावी सुधारों का ब्लू प्रिंट भी देश के सामने प्रस्तुत करना चाहिए।

हमारी दो राज्य सरकारों – उत्तराखंड (पूर्ववर्ती) और हिमाचल प्रदेश ने अपने–अपने राज्यों में प्रभावी और मजबूत लोकायुक्त विधेयक पारित करने का प्रशंसनीय काम किया है। हमें इन साहसी कदमों को जनता में लोकप्रिय बनाने का काम करना चाहिए।

नक्सली बंधक समस्या (जिलाधिकारी एलेक्स पॉल मेनन समेत) से मजबूती और सफलता से निपटने के लिए हमें अपनी छत्तीसगढ़ सरकार को बधाई देने के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा के इस गंभीर खतरे से निपटने के लिए राष्ट्र के सम्मुख व्यापक उपाय भी प्रस्तुत करने चाहिए।

भाजपा की समस्या–निराकरण की प्रतिबद्धता का प्रमाण हमारी गुजरात सरकार की उपलब्धियों और कार्यों में भी दिखता है, जहां कृषि का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ, सौराष्ट्र और कच्छ में पानी की स्थायी समस्या को हल किया गया, सौर ऊर्जा, महिला साक्षरता, जनजातीय कल्याण और इसी तरह के अन्य मामलों में हमने देश के सामने मिसाल पेश की है।

यही क्रम कर्नाटक में सुशासन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाने में, बिहार में ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को बेहतर बनाने में, और मध्यप्रदेश में सिटीजन चार्टर के प्रभावी क्रियान्वयन तथा अमल में भी दिखता है।

मीडिया सहित अनेक प्रतिष्ठानों के अध्ययनों में सन 2000 से भाजपा–एनडीए शासित राज्य सरकारों को अनेक मानकों पर कांग्रेस और वामपंथी सरकारों की तुलना में बेहतर पाया गया है। इन संस्थाओं द्वारा दिये गये पुरस्कारों में हमारी सरकारें अव्वल रही हैं।

क्षेत्रीय पार्टियों के प्रति भाजपा का सैद्धांतिक नज़रिया

क्षेत्रीय पार्टियों के बारे में हमारा रवैया स्पष्ट है। हमारा मानना है कि इन दलों की सोच भी राष्ट्रीय होती है। वास्तव में इनमें से कई एनडीए में भाजपा के महत्वपूर्ण सहयोगी रहे हैं।

एनडीए के शासन ने यह दिखा दिया है कि स्थायी और उद्देश्यपूर्ण सरकार तभी संभव है जब सत्तारूढ़ गठबंधन के केंद्र में भाजपा की तरह राष्ट्रीय और राष्ट्रवादी पार्टी मजबूत रूप में हो।

हमें यह बात लोगों को खासतौर पर समझानी होगी कि केंद्र में अस्थिरता की बड़ी भारी कीमत राष्ट्र की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को चुकानी पड़ती है। इस कारण हमें लोगों को समझाना होगा कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर आधारित भाजपा के नेतृत्व वाली मजबूत गठबंधन सरकार ही एकमात्र सच्चा विकल्प है, जो नई दिल्ली में सरकार परिवर्तन की आकांक्षा को पूरा कर सकती है।

भाजपा ही एक विकल्प,
जिसकी तलाश भारत की जनता को है

सार्थक विकल्प के पांच निर्धारक तत्व होते हैं:

(क) सशक्त, सक्षम और विश्वसनीय नेतृत्व जिसमें टीम भावना हो और जो देश को पार्टी से ऊपर और पार्टी को स्वयं से ऊपर रखता हो;

(ख) देश के सम्मुख आसन्न चुनौतियों और अवसरों को समझने की दूरदर्शिता;

(ग) सही फैसले लेने की क्षमता और जन समर्थन से उन्हें लागू करना;

(घ) पारदर्शी और ईमानदार कार्यपद्धति; और

(ड़) राष्ट्रवाद, सुशासन, विकास और अंत्योदय हेतु प्रतिबद्धता।

गांव, गरीब, किसान और मजदूर की समग्र उन्नति–अंत्योदय के मूल वाले हमारे विकास विज़न में हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रखती है। स्वामी विवेकानंद ने हमसे कहा था:

"जब तक लाखों लोग भूख और अज्ञानता में जीवन बिता रहे हैं, तब तक मैं हर उस व्यक्ति को देशद्रोही कहूंगा जिसने उन लोगों के खर्चे पर पढ़ाई की और उन्हीं की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देता।"

अगले वर्ष स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती मनाई जाएगी। मैं पार्टी की सभी इकाइयों से अनुरोध करता हूं कि वे इस पवित्र अवसर पर देश के कोने–कोने में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करें। हमें यह दिखाना है कि राजनीति के क्षेत्र में भाजपा, स्वामीजी के जागृत भारत के संदेश की सर्वश्रेष्ठ वाहक है।

हमारी पार्टी लोगों का विश्वास उस हद तक जीत

पाएगी जिस हद तक हम उक्त खूबियों को भाजपा में – केंद्र में, राज्य में और स्थानीय स्तरों पर निरंतर विकसित करते चले जाएंगे। लोगों के विश्वास के बल पर, और इससे मिलने वाली राजनीतिक ताकत के आधार पर, राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न पहलुओं में व्यापक बदलाव लाने की जो हमारी सोच है उसे अमल में ला सकेंगे।

भाजपा के हम सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को राजनीति में अपनी भूमिका को एक संकुचित और अल्पकालिक परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना चाहिए। हमारे लिए राजनीति दूरगामी सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन का एक माध्यम है। हमें खुद को इस भूमिका के योग्य बनाना है।

क्योंकि आज की वंशवादी और भ्रष्ट कांग्रेस भारत की तरक्की और विकास की राह का सबसे बड़ा रोड़ा बन गई है। इसके लिए यह आवश्यक है कि कांग्रेस को केंद्र की सत्ता से उखाड़ फेंकें।

हमारा रणनीतिक लक्ष्य : भाजपा के वोट प्रतिशत में कम से कम १०: की वृद्धि और एनडीए का विस्तार

जैसाकि पिछले दो वर्षों में मैंने कई अवसरों पर गौर किया है कि, कांग्रेस को बेदखल करने की हमारी रणनीति तीन अनिवार्य शर्तों पर निर्भर करती है: (क) जिन राज्यों में हम पारंपरिक तौर पर कमज़ोर हैं, उनमें भाजपा के जनाधार का विस्तार (ख) भाजपा के संपूर्ण वोट आधार में कम से कम 10 प्रतिशत की वृद्धि और (ग) एनडीए का विस्तार।

तीनों ही लक्ष्यों को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर – वैचारिक, राजनीतिक और संगठनात्मक मोर्चों पर कुछ आवश्यक कदम उठाने होंगे।

इन मुद्दों पर हमारी सोच और कार्य में कुछ उत्साहवर्द्धक प्रगति हुई है। हमारे कई मोर्चों और प्रकोष्ठों ने पिछले कुछ महीनों में सराहनीय कार्य किये हैं। किसान मोर्चे ने इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रीय राजधानी में एक सफल 'किसान संसद' का आयोजन किया। बुनकर प्रकोष्ठ ने हाल ही में 'समर शंखनाद' नाम का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जिसमें बुनकरों की दयनीय स्थिति और उनके संघर्ष की बात खुलकर सामने आई। मछुआरा प्रकोष्ठ भी सक्रिय है। उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ ने भी भाजपा सरकारों की उपलब्धियों के प्रदर्शन के लिए एक आयोजन किया, जिसमें करीब 500 कारोबारी शामिल हुए।

मज़दूर महासंघ ने देश भर में कई आंदोलनों और अभियानों का नेतृत्व किया। पिछले वर्ष ऐसे ही एक आयोजन में करीब 500 से ज्यादा ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि शामिल हुए थे।

इनमें से हर एक सम्मेलन और आयोजन में, हम कांग्रेस सरकार की नाकामियों और धोखाधड़ी की सिर्फ आलोचना नहीं करते। हम ऐसे ठोस समाधान भी सुझाते हैं जिन्हें अगर भाजपा को अगली सरकार बनाने का मौका दिया गया तो, वो पूरी प्रतिबद्धता से लागू किए जाएंगे। अगर हमारा व्यापक संगठनात्मक ढांचा इन गतिविधियों का संदेश ज़मीनी स्तर तक ले जाएगा तो समाज के विभिन्न वर्गों में भाजपा के प्रति लोगों की सद्भावना को बल मिलेगा।

आने वाले महीनों में, हमने असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों – शिक्षकों, डॉक्टरों, व्यापारियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इत्यादि के लिए विशाल राष्ट्रीय सम्मेलनों की योजना बनाई है।

मैं अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र के करीब 45 करोड़ श्रमिकों के बीच तेज़ी से फैल रहे हमारे कार्य को विशेष महत्व के साथ बताना चाहता हूं। हमें खेतिहर मजदूरों, निर्माण कार्य में लगे मजदूरों, ढुलाई करने वालों, रिक्शाचालकों, घरों में कार्य करने वाली महिलाओं (मेड सर्वेंट्स) और इसी तरह के अन्य सभी लोगों को विश्वास दिलाना है कि भाजपा ही उनकी पार्टी है।

जब हम इस कार्य में सफल होंगे तो हमारा वोट प्रतिशत स्वाभाविक रूप से निरंतर बढ़ता जाएगा। इस संदर्भ में, मैं दक्षिण के तमिलनाडु की एक उत्साहवर्द्धक घटना का उल्लेख विशेष तौर पर करना चाहता हूं। हमारी पार्टी ने मदुरै में हाल ही में विशाल सम्मेलन किया जिसमें एक लाख से अधिक कार्यकर्ता शामिल हुए। इस सफलता के लिये मैं राज्य इकाई को बधाई देता हूं।

हाल के चुनावों में भाजपा का प्रदर्शन

अब मैं, हमारी पिछली बैठक के बाद हुए चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन की बात करूंगा।

चूंकि हम मुंबई में बैठक कर रहे हैं, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि मेरे साथ राज्य और शहर की पार्टी यूनिट को हाल में हुए मुंबई म्यूनिसिपल चुनावों में शानदार सफलता पर बधाई दें। अपने गठबंधन के साथियों शिव सेना और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) के साथ मिलकर हमने मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में हुए चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया। मुझे कोई संदेह नहीं कि ये सफलता उस बड़ी सफलता की शुरुआत भर है जो हमारी पार्टी और हमारे गठबंधन को – कांग्रेस–एनपीसी के भयंकर रूप से भ्रष्ट और अक्षम शासन को अगले विधानसभा चुनावों में समाप्त कर मिलने वाली है।

इसी तरह मैं इस मौके पर भाजपा की दिल्ली प्रदेश इकाई को भी बधाई देना चाहूंगा जिसे हाल ही में हुए नगर निगम चुनावों में जबरदस्त जीत मिली है। ये जीत भी, सन्

2013 में होने वाले विधान सभा चुनावों में पार्टी की इससे भी बड़ी जीत की शुरुआत है।

पड़ोसी राज्य गोवा में, भाजपा ने हाल के विधान सभा चुनावों में कांग्रेस को सत्ता से हटाने में कामयाबी हासिल की है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर परिकर, श्री श्रीपाद नाईक और श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर तथा गोवा के तमाम कार्यकर्ताओं का मैं दिल से अभिनंदन करता हूं। गोवा में हमारी जीत दो वजहों से खास है। पहला, हमें वहां पूर्ण बहुमत मिला है। लिहाजा, कांग्रेस पार्टी को सरकार गिराने का मौका नहीं मिलेगा – जो खाली वक्त को बिताने के लिए उसका एक पसंदीदा काम बन गया था। दूसरा, इस बार हमारी पार्टी गोवा में एक बड़े वर्ग का समर्थन पाने में सफल हुई है, जबकि कांग्रेस ने अपने हित के लिए ये दुष्प्रचार किया कि भाजपा अल्पसंख्यक विरोधी है। यह विशेष उल्लेखनीय है कि हमारे 9 विधायक अल्पसंख्यक समाज के प्रतिनिधि हैं।

गोवा के अनुभव से सीख लेते हुए, मैं अपनी पार्टी की सभी इकाइयों से ये अपील करूंगा कि वे अल्पसंख्यक समुदाय के हमारे बंधुओं का भरोसा जीतने के ऐसे ही प्रयास तेज करें। मैं अपने अल्पसंख्यक बंधुओं से विशेष तौर पर अपील करता हूं और उन्हें आश्वासन देता हूं: "कांग्रेस और कम्युनिस्टों के इस स्वार्थपूर्ण दुष्प्रचार में मत फंसिए कि भाजपा अल्पसंख्यक विरोधी पार्टी है। अगर भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन अगली सरकार बनाता है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हम आपकी सुरक्षा, विकास और भलाई का उसी तरह से ख्याल रखेंगे, जिस तरह से अन्य समुदायों का रखते हैं। जाति, नस्ल, भाषा या लिंग के बिना किसी भेदभाव के हम सभी भारतीयों को आर्थिक और सामाजिक न्याय सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 'एकात्म मानववाद' से हमने यही पाठ सीखा है।"

हम पंजाब के अपने साथियों और अपने गठबंधन के सहयोगी – शिरोमणि अकाली दल का भी गर्मजोशी से अभिनंदन करें जिन्होंने राज्य में नए सिरे से जनादेश हासिल करने की उल्लेखनीय उपलब्धि अर्जित की है।

मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में हमारी पार्टी ने महबूबनगर विधानसभा उपचुनाव में भी उल्लेखनीय जीत हासिल की है।

उत्तराखंड में हम मात्र एक सीट से सरकार बनाने से चूके। इन परिणामों का हमें अध्ययन करना होगा।

उत्तर प्रदेश में परिणाम हमारी अपेक्षाओं से कम रहे। राज्य की जनता बदलाव चाहती थी। लेकिन हम अपने आप को एक भरोसेमंद और मजबूत विकल्प के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सके। यद्यपि प्रदेश में हमारा प्रदर्शन अपेक्षा अनुरूप नहीं रहा लेकिन अभी भी प्रदेश में हमारा व्यापक जनाधार है। मुझे विश्वास है कि हमारे प्रयासों से फिर से हमारे साथ जुड़ेगा। प्रदेश में पार्टी को हर स्तर पर युवाओं को भी आगे लाना होगा। इस दिशा में हमारे प्रयास शुरू हो गए हैं।

तत्काल हमारे सामने गुजरात और हिमाचल प्रदेश में आने वाले चुनावों का सफलतापूर्वक सामना करने की चुनौती है। हमारी अन्य सरकारों की भांति गुजरात और हिमाचल प्रदेश सरकारों ने सुशासन के नए–नए कीर्तिमान स्थापित कर व्यापक सराहना पाई हैं। गुजरात ने खास तौर पर, अपने तीव्र और चौतरफा विकास से पूरे देश और दुनिया की नजरों में अपना स्थान बनाया है। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी की इकाइयां दोनों ही राज्यों में एक बार फिर लोगों का समर्थन और जनादेश हासिल करने में सफल रहेंगी।

राष्ट्रपति चुनाव

इस वर्ष जुलाई में 13वें राष्ट्रपति का चुनाव होना है। भाजपा यह प्रयास कर रही है कि गैर–कांग्रेसी दलों में एक व्यापक आम सहमति बने ताकि एक ऐसे योग्य उम्मीदवार को खड़ा किया जाए जो संविधान की रक्षा करने के साथ–साथ, गणतंत्र के सर्वोच्च पद को और गरिमामय बना सके। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपति भवन में आसीन होने वाले उम्मीदवार का चयन मुख्य रूप से इस कसौटी पर कर रही है कि वह एक परिवार विशेष के प्रति स्वामीभक्ति रखता हो, न कि संविधान के प्रति। जिस तरह कांग्रेस ने भारतीय लोकतंत्र के दूसरे संस्थानों की गरिमा को कम किया है, उसी तरह वह राष्ट्रपति पद की गरिमा कम करना चाहती है। इस बार इसे किसी हाल में सफल होने नहीं देना चाहिए।

पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण

मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा प्रशिक्षण विभाग एक प्रकार से इतिहास रच रहा है, जो हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरे जोर शोर से आगे बढ़ाने वाला है। सन् 2012 की शुरुआत के बाद से ही, पांच राज्यों में चुनावों की वजह से, हम अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम को सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे थे। लेकिन अब, हम एक बार फिर इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं। मेरा अंदाजा है कि हमारा सुसंगठित प्रशिक्षण कार्यक्रम हाल के चुनावों में पार्टी के लिए काफी फायदेमंद रहा है। उत्तराखंड के सभी जिलों में 'प्रवेश वर्ग' आयोजित किए गए, पंजाब में सभी विभागों और गोवा में दो राज्य स्तर के वर्ग लगाए गए। दिल्ली में 200 से ज्यादा मंडलों में एक दिन के मंडल अभ्यास वर्गों में 30,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इसका नतीजा आज सबके सामने है।

प्रशिक्षण का दूसरा स्तर जिसे 'प्रगत वर्ग' कहा जाता है, उसकी शुरुआत जून, 2012 से हो रही है। पहले 'प्रगत वर्ग' में हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी शामिल होगी जिसका आयोजन 15 से 18 जून के बीच मध्यप्रदेश में होगा। इसके बाद अंडमान और अन्य राज्यों में आयोजन होंगे। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि इस जोश को बनाए रखें। मैं देश के विभिन्न हिस्सों में सन् 2012–2013 के दौरान होने वाले 'प्रवेश वर्ग' और 'प्रगत प्रशिक्षण' वर्गों से भी और अधिक उम्मीद कर रहा हूं।

इस मौके पर मैं अपने सभी स्तर के पदाधिकारियों से यह अपील करना चाहूंगा कि उन्हें इसकी पहल करनी है और ये सुनिश्चित करना है कि प्रशिक्षण के कार्यक्रम योजना के मुताबिक चलें और हम उन लक्ष्यों को हासिल करें जो हमने तय किए हैं।

हमारे सुशासन प्रकोष्ठ के कार्य भी सही मायने में सराहनीय हैं। अप्रैल में, इसने पहली बार राज्य स्तर के खादी और ग्रामीण उद्योग परिषदों और हैंडलूम तथा हैंडीक्राफ्ट बोर्ड के अध्यक्षों और सदस्यों की एक बैठक का आयोजन किया। 'सुशासन प्रकोष्ठ' ने एक नए विचार पर काम करना शुरु किया है जिसमें हमारी सरकारों के उत्कृष्ट कार्यों को छोटे–छोटे लेखों और छोटी डॉक्यूमेंट्री वीडियो फिल्मों के जरिए संकलित जा रहा है, और जिसे "द डिफरेंस दैट वी मेड" शीर्षक दिया गया है। इस श्रृंखला का पहला मोनोग्राफ छत्तीसगढ़ में सफलतापूर्वक लागू की गई सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) पर था, जिसका प्रकाशन इसी वर्ष किया गया है। गुजरात के अहमदाबाद में बीआरटीएस को सफलतापूर्वक लागू किए जाने पर तैयार की गई एक लघु फिल्म इसी बैठक में रिलीज़ की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण के संरक्षण पर एक मोनोग्राफ भी इस मीटिंग में रिलीज़ किया जाएगा। इसी प्रकार मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, पंजाब और गोवा में हमारी सफलताओं सम्बन्धी मोनोग्राफ पर भी काम चल रहा है।

मैंने 'सुशासन प्रकोष्ठ' से कहा है कि वह जल्द ही 'ई–गवर्नेंस के जरिए सुशासन' विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करे।

मैं यहां आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हमारा 'ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी' भी अच्छा काम कर रहा है। पिछले वर्ष नवंबर में, 'ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी', अमेरिका ने हमारे वहां के कार्यकर्ताओं के लिए दो प्रशिक्षण सत्र चलाए। उन्होंने अमेरिका में भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावासों में काउंसिल द्वारा दी जा रही सेवाओं पर एक सर्वे भी किया है। विदेशों में राजनीतिक दलों से पार्टी स्तर पर संबंध बनाने के लिए, हमने अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी के छह सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल की इसी वर्ष जनवरी में मेजबानी की। ये प्रतिनिधिमंडल पहले मुंबई पहुंचा जहां रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी द्वारा आयोजित एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हिस्सा लिया। बाद में, वे अहमदाबाद गए जहां उन्होंने गुजरात में भाजपा सरकार द्वारा बेहतर शासन के लिए उठाए गए कुछ कदमों को करीब से देखा। दौरा खत्म होने से पहले, उनका दल दिल्ली में हमारे पार्टी मुख्यालय आया जहां उनकी बातचीत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं से हुई।

जनवरी में, हमने एक 'आईपी टीवी' या 'इंटरनेट टीवी चैनल' की शुरुआत की है जिसे 'युवा टीवी' नाम दिया गया है। ये हमारे आईटी प्रकोष्ठ का एक सराहनीय कदम है। इसके जरिए हमारी कोशिश देश के युवाओं तक अपनी पहुंच बनाने की है। जैसाकि आप सभी जानते हैं, युवाओं का हिस्सा हमारी आबादी में करीब 35 प्रतिशत है और हमें उन तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश करनी होगी। मैं अपने सभी युवा मोर्चा के सदस्यों को अपील करना चाहूंगा कि वे इस चैनल की कार्यवाहियों में बढ़–चढ़कर हिस्सा लें और इसके जरिए हमारे नए मतदाताओं की उम्मीदों पर खरा उतरें।

यहां यह उल्लेख करना भी जरूरी है कि हमारे पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ और रक्षा प्रकोष्ठ ने भी उत्तराखंड चुनावों में मतदाओं से संपर्क बनाने में सराहनीय कार्य किया।

भाजपा विज़न दस्तावेज 2025

हम केवल अगले चुनाव पर लक्ष्य केंद्रित करने वाल पार्टी नहीं हैं। हमारी सोच, लक्ष्य और प्रतिबद्धता दूरगामी हैं, और वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 'एकात्म मानववाद' के दर्शन से निर्देशित और प्रेरित है, जो भारत के भूत, वर्तमान और भविष्य को एक सभ्यतागत नजरिए से देखता है।

इसी प्रकार, पार्टी ने देश के लिए एक विज़न 2025 दस्तावेज (डॉक्यूमेंट) तैयार करने और सार्वजनिक करने का फैसला किया है। इसमें भाजपा का भविष्य का दृष्टिकोण, विचार और प्रतिबद्धताओं को प्रस्तुत किया जाएगा। 'भारत को सशक्त, समृद्ध और सद्भावपूर्ण राष्ट्र बनाना, जो 21वीं सदी के विश्व की नियति निर्धारित करेगा'–यह इसका प्रमुख उद्देश्य है। इस दस्तावेज़ में बड़े और महत्वाकांक्षी विचार होंगे, और उनके साथ ही उन्हें लागू करने का एक व्यावहारिक खाका भी होगा।

मुझे विश्वास है कि भाजपा का 'विज़न 2025' दस्तावेज़ हमारे तमाम कार्यकर्ताओं और समर्थकों को उन सभी मुद्दों पर एक दृष्टिकोण और लक्ष्य तय करने में मदद करेगा जिन मुद्दों पर देश के विवेकपूर्ण लोग पहले ही गंभीरता से बहस कर रहे हैं। ये भाजपा की छवि एक प्रेरणादायक दृष्टिकोण

वाली पार्टी के तौर पर उभारने में भी मदद करेगा।

इस प्रकार के कार्य के लिए सभी की भागीदारी आवश्यक है। इसमें देश भर के और विदेशों में सक्रिय भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ–साथ विविध विषयों के विचारकों को भी शामिल किया जाना चाहिए, वे निश्चित तौर पर इस योजना में अपना योगदान देने में गौरवान्वित महसूस करेंगे। 'विज़न 2025' दस्तावेज़ को तैयार करने के लिए एक टीम का गठन किया गया है। उम्मीद है कि ये टीम अपना काम दीनदयालजी की जयंती – 25 सितंबर से पहले पूरा कर लेगी।

दीनदयाल भवन : नया भाजपा मुख्यालय

मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। भारत सरकार सभी बड़े राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय मुख्यालयों के लिए ज़मीन का आवंटन कर रही है। इसी के तहत, हमारे लिए राष्ट्रीय राजधानी के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर दो एकड़ का प्लॉट मंजूर किया गया है। हम इस प्लॉट पर एक भव्य कार्यालय बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जिसमें पार्टी का कार्यालय, प्रशिक्षण और अनुसंधान एवं विकास की तीन इकाईयां होंगी।

एक स्थायी प्रदर्शनी इस भवन की विशिष्टता होगी जिसमें भाजपा की विचारधारा और अब तक की यात्रा दर्शायी जाएगी। इस प्रदर्शनी में भारत की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने के लिए हुए हमारे आंदोलनों और संघर्षों को भी दिखाया जाएगा। ये हमें याद दिलाएगी कि कैसे हमारे नेताओं ने लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष और त्याग किए। भारतीय राजनीति की समृद्ध विरासत में हमारे योगदान को भी प्रस्तावित प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाएगा।

ये कार्यकर्ताओं का, कार्यकर्ताओं के द्वारा और कार्यकर्ताओं के लिए एक निर्माण होगा! इसी वजह से, यह तय किया गया है कि ये भवन हमारे लाखों कार्यकर्ताओं के निजी योगदानों से तैयार किया जाएगा। इस अवसर पर मैं आप सभी से इस ऐतिहासिक अभियान में शामिल होने की अपील करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी क्षमता के अनुसार इस महत्वाकांक्षी परियोजना में योगदान करेंगे। डा़ श्यामाप्रसाद मुकर्जी के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में इस अभियान की शुरुआत होगी।

निष्कर्ष

वर्ष 2013 अनेक कारणों से महत्वपूर्ण है। यह स्वामी विवेकानन्द की 150वीं जयंती का वर्ष है। दुनियाभर के करोड़ों लोगों के लिए स्वामीजी सदैव प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। उन्हें अपनी आदरांजलि देते हुए मैं पार्टी की सभी इकाईयों को नई–नई योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को राष्ट्रीय पुनरूद्धार के लिए प्रेरित करने हेतु स्वामी विवेकानन्द के योगदान का स्मरण कराएं। मैं अपनी सभी प्रदेश इकाइयों से अपील करूंगा कि वे स्वामीजी का स्मरण करते समय बहुविध लोगों को इसमें जोड़ें। हमारे लिए हिन्दुत्व स्वामीजी की सीखों पर आधारित है। हमारे लिए हिन्दुत्व दूरदृष्टि, वैज्ञानिक और विकासोन्मुखी का पर्याय है। वास्तव में हिन्दुत्व और विकास अविभाज्य हैं। आइए, इस अवसर पर हम अपने को राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में फिर से समर्पित करें।

हमारा देश इस समय ऐसे कठिन दौर से गुजर रहा है, जिसके लिए यूपीए का कुशासन मुख्य रूप से जिम्मेदार है। देश में इस वक्त हालात ऐसे हैं कि लोग कांग्रेस की विदाई देखना चाहते हैं। वो बदलाव चाहते हैं और गंभीरता से एक सही विकल्प की तलाश कर रहे हैं। उन्हें भाजपा से बड़ी आशाएं और उम्मीदें हैं। अगर हम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे, वे हमें अगली सरकार बनाने और देश की सेवा करने का का जनादेश अवश्य देंगे।

इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक बात और। हमें अपने आपको फिर से याद दिलाना है कि हम राजनीति में केवल सत्ता के लिए नहीं हैं। राजनीति हमारे लिए राष्ट्रनिर्माण और समग्र सामाजिक विकास का साधन है। इसलिए, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि सारे छोटे–छोटे मुद्दों को किनारे रखकर भाजपा की मजबूती के लिए काम करें क्योंकि नियति ने हमारे सामने चुनौतियां और अवसर–दोनों प्रस्तुत किए हैं। हम असफल नहीं हो सकते। हमें सफल होना ही है।

इस संदेश को चरितार्थ करने के लिए मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यों से अपील करता हूं कि वे पार्टी संगठन को मज़बूत बनाने के काम में अपने को पुनः समर्पित करें। मैंने भी प्रत्येक प्रदेश में जाकर वहां संगठनात्मक कोर टीम, पदाधिकारियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ व्यक्तिगत संवाद करने का निर्णय किया है। प्रत्येक प्रदेश का दो दिवसीय दौरा आनेवाले दिनों में सुसंगठित रुप से चलेगा।

जैसाकि मैंने शुरुआत में कहा था, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यह बैठक अगले संसदीय चुनावों के लिए हमारी तैयारियों को शुरू करने के लिए है। मैं सफलता का एक साधारण लेकिन सटीक मंत्र देना चाहूंगा – हम अपनी एकता, अनुशासन और समर्पण को हर स्तर पर सुदृढ़ करें।

आइए! हम सब अटलजी की भविष्यवाणी को एक छोटे से संशोधन के साथ एक बार फिर सच कर दिखाएं।

''अंधेरा छंटेगा, कार्यकर्ता जुटेगा,
सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा!''

èkU ; okn!

onekr je! ■

सूखे की समस्या के प्रति यूपीए का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण

भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में 'सूखे की स्थिति सम्बंधी प्रस्ताव' सर्वसम्मति से पारित किया गया, जिसे भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वेंकैया नायडू ने रखा एवं इसका अनुमोदन महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री सुधीर मुंगतीवार, कर्नाटक प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री के.एस. ईश्वरप्पा एवं आन्ध्र प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री जी. किशन रेड्डी ने किया। इस प्रस्ताव के माध्यम से पार्टी ने देश के विभिन्न भागों में, विशेष रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश–मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में, जो सूखे से बुरी तरह से प्रभावित हैं, सूखे की गंभीर स्थिति पर गहरी चिन्ता व्यक्त की है। साथ ही, लोगों के दुःख–तकलीफों के प्रति केन्द्र सरकार की उदासीनता पर भी गहरी निराशा प्रकट की है। हम इस प्रस्ताव का पूरा पाठ यहां प्रस्तुत कर रहे हैं :–

Hkkरतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी देश के विभिन्न भागों में, विशेषरूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश–मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में, जो सूखे से बुरी तरह से प्रभावित हैं, सूखे की गंभीर स्थिति पर गहरी चिन्ता व्यक्त करती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी लोगों के दुःख–तकलीफों के प्रति केन्द्र सरकार की उदासीनता पर भी गहरी निराशा व्यक्त करती है।

सूखे से कई प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं और इसका अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप खाद्य की कमी, चारे की कमी, पानी की कमी, कृषि उत्पादन और आय में कमी, खाद्य और अन्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि, कृषि और इससे सम्बन्धित क्षेत्रों में बेरोजगारी हो जाती है, जिसके कारण पलायन होता है। कृषि ऋणों का भुगतान नहीं होता, ग्रामीण असन्तोष आदि पनपता है।

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र भयंकर सूखे की स्थिति का सामना कर रहा है। पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ हिस्से और विदर्भ क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित है। राज्य सरकार ने खरीफ के लिए 15 जिलों (209 तालुकों) और 6205 गांवों को और रबी की फसलों के लिए 1552 गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया है।

खरीफ के अन्तर्गत प्रभावित क्षेत्र 20.40 लाख हेक्टेयर है और इसमें 14,62,937 किसान प्रभावित हुए है जबकि रबी फसल उत्पादन 10.77 लाख हेक्टेयर बैठता है और इसमें 80,40,57 किसान प्रभावित हैं।

कृषि परियोजनाओं के जल स्तर तथा भू–जल स्तरों में भारी गिरावट आई है। 23 तालुकों में भू–जल स्तरों में 1–2 मीटर की कमी हुई है, 9 तालुकों में 2–3 मीटर के बीच की कमी हुई है, जबकि 6 तालुकों में भू–जल स्तर में 3 मीटर से अधिक की कमी हुई है। पीने के पानी की सप्लाई टैंकरों के माध्यम से की जा रही है।

खाद्यान्नों, तिलहनों, कपास और गन्ने के उत्पादन में भारी गिरावट आई है। अनाजों के उत्पादन में 5 प्रतिशत, दालों के उत्पादन में 22 प्रतिशत और खाद्यान्नों के उत्पादन में 5 प्रतिशत की कमी होने का अनुमान है। रबी–ज्वार के अनुमानित उत्पादन में भी सामान्य से और गत वर्ष की तुलना में क्रमशः 11 और 26 प्रतिशत की कमी होगी। पशुधन के लिये चारे की भारी कमी है। 13 जिलों में बागवानी पर सूखे का बुरा प्रभाव पड़ा है, जहां पर अनार, अंगूर, आम, संतरा, मौसमी जैसे फलों के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा है। अपर्याप्त वर्षा के कारण उत्पादन में भारी कमी हुई है।

महाराष्ट्र में सूखे की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने केन्द्र से 2281.37 करोड़ रुपए की कुल सहायता और राज्य को यथाशीघ्र गरीबी रेखा से नीचे की

दरों पर 5 लाख मीटरिक टन अनाज दिये जाने का अनुरोध किया है। यद्यपि केन्द्र की एक टीम ने राज्य का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया है, तथापि अभी तक केन्द्रीय सहायता प्रदान नहीं की गई है।

कर्नाटक

कर्नाटक का 70 प्रतिशत भाग अर्थात् 176 में से 123 तालुका सूखा प्रभावित घोषित किये गये हैं। वहां पर पानी और चारे की कमी है। गत तिमाही में 1970 से अब तक वर्षा सबसे कम हुई है।

खरीब और रबी दोनों फसलें बर्बाद हो गई हैं। कुल 5953 करोड़ रुपए की फसल की हानि का अनुमान है। बहुत कम वर्षा, सूखे की स्थिति और अधिक नमी से राज्य के अन्दरूनी हिस्सों में न केवल खरीफ की फसल प्रभावित हुई है अपितु रबी की फसल भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। भू–जल स्तर दिन–प्रतिदिन गिरता जा रहा है। अधिकांश बोर कुएं सूख गये हैं। 700 बोर कुओं में से केवल 5 कुएं काम कर रहे हैं।

कुछ क्षेत्रों में 1250 फुट की गहराई पर भू–जल उपलब्ध है। भू–जल स्तर आज तक के रिकार्ड से भी नीचे चला गया है और वह पानी पीने लायक नहीं है। फ्लोराइड और आर्सेनिक सामग्री की उच्च मात्रा से स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएं पैदा हो रही हैं।

4853 गांवो में पीने के पानी की भंयकर समस्या है। राज्य सरकार सैकेड़ों प्रभावित गांवों को टैंकरों के माध्यम से पीने के पानी की सप्लाई कर रही है। 3475 छोटे सिंचाई टैंकों में से 1242 टैंक पूरी तरह से सूख गये हैं।

राज्य सरकार ने सूखे से निपटने के लिये अभी तक 562.55 करोड़ खर्च किये हैं। सूखा राहत उपायों के लिये राज्य सरकार ने प्रथम चरण में 2605.99 करोड़ रूपये की केन्द्रीय सहायता की मांग की ओर बाद में 5953 करोड़ रूपये के लिये एक ज्ञापन केन्द्र को सौंपा। केन्द्र ने 186.68 करोड़ रूपये की स्वीकृति दे दी है और अभी तक 70.23 करोड़ रूपये की राशि रिलीज की है। यह बड़ी खेदजनक बात है कि केन्द्र ने पहली बार ही 116.45 करोड़ रूपये की शेष राशि रिलीज नहीं की है।

सूखा इतना भंयकर है कि केन्द्र की सहायता के बिना अकेला राज्य इस अप्रत्याशित स्थिति से नहीं निपट सकता। राज्य सरकार ने 1500 करोड़ रूपये की अन्तरिम राहत की मांग की थी, जो अभी तक नहीं दी गई है। राज्य ने गरीबी रेखा के नीचे के कार्डधारियों को अनाज बांटने के लिये 3,00,000 मीटरिक टन चावल और 57,000 मीटरिक टन गेहूँ का अतिरिक्त आवंटन करने की भी मांग की है।

केन्द्रीय टीम अब राज्य का दौरा करने जा रही है जबकि मानसून तेजी से आ रहा है। इससे केन्द्र के कठोर रवैये का पता चलता है।

आन्ध्र प्रदेश

समूचा आन्ध्र प्रदेश राज्य सूखे से प्रभावित है। 22 जिलों में 876 मण्डल सूखाग्रस्त घोषित किये गये हैं। 34.24 लाख हेक्टेयर क्षेत्र (छोटे और सीमांत किसानों का 29.75 लाख हेक्टेयर और अन्य किसानों का 4.49 लाख हेक्टेयर) बर्बाद हो गया है। 49,31,701 छोटे और सीमांत किसान और 3,06,259 अन्य किसान प्रभावित हुए हैं।

30,98,560 मीटरिक टन कृषि उत्पाद नष्ट हुए हैं। इसका अनुमानित मूल्य 5747 करोड़ रूपये हैं। फसल ऋणों का पुनः निर्धारण नहीं किया गया है। किसान प्रति एकड़ इन्पुट सब्सिडी के रूप में 10,000 की मांग कर रहे हैं। यहां तक कि प्रभावित क्षेत्रों में वृद्धावस्था पैंशन भी उचित तरीके से नहीं दी जा रही है।

एन.डी.आर.एफ. से केन्द्रीय सहायता के रूप में 3,006 करोड़ रूपये की कुल राशि केन्द्र सरकार से मांगी गई थी। भारत सरकार ने 706.15 करोड़ रूपये की केन्द्रीय सहायता की स्वीकृति प्रदान की है जिसमें 385.78 करोड़ रूपये की राशि रिलीज की गई और शेष राशि का राज्य के एस.डी. आर.एफ. खाते में समायोजन किया गया है।

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने दिसम्बर 2011 में 1860 करोड़ रूपये की इन्पुट सब्सिडी देने का वादा किया था। अभी तक वह राशि रिलीज नहीं की गई। जिन किसानों को 2010–11 के रवी मौसम में हानि हुई थी, उन्हें अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। यहां तक कि रबी की फसल में भी 10 प्रतिशत की कमी आई है।

भाजपा इस बात पर गहरी चिन्ता व्यक्त करती है कि सूखे की गम्भीर समस्या के प्रति केन्द्र सरकार का रवैया बहुत ही गैर–संजीदा और कठोर है। विभिन्न राज्यों में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिये केन्द्रीय टीमों को भेजने में असाधारण विलम्ब हुआ है। यही नहीं, सरकार टीमों की सिफारिशों पर समय से कार्यवाही नहीं करती। देश के अनेक भागों में बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और टीमों को बहुत देरी से भेजने का कोई लाभ नहीं है। इससे लोगों के दुःख– तकलीफों के प्रति केन्द्र सरकार की उपेक्षापूर्ण और असंवेदनशील रवैये का पता चलता है। इस प्रस्ताव को भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री एम. वेंकैया नायडू ने प्रस्तावित किया तथा महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्षों ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। भाजपा मांग करती है कि –

शेष पृष्ठ 21 पर

कृषि संकट से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में यूपीए विफल

बैठक में सर्वसम्मति से कृषि सम्बंधी प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने प्रस्तुत किया और इसका समर्थन मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। इस प्रस्ताव के माध्यम से कहा गया है कि भारत को एक ऐसे आर्थिक मॉडल की आवश्यकता है जो संतुलित विकास पर केन्द्रित हो तथा वह देश में लोगों की आमदनी में गहरा असंतुलन न पैदा करती हो। हमें किसान केन्द्रित आर्थिक मॉडल की आवश्यकता है क्योंकि विकास के पश्चिमी मॉडल हमारे देश के लिए उपयुक्त नहीं है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि सरकार को कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली सब्सिडी को वित्तीय अनुशासन के नाम पर समाप्त नहीं करना चाहिए। पार्टी ने मांग की है कि उर्वरक सब्सिडी सीधे किसानों को मिलनी चाहिए और इस संबंध में सरकार को 'फॉलोअप एक्शन' लेना चाहिए। जैविक कृषि के लिए भी सब्सिडी का प्रावधान होना चाहिए। प्रस्तुत है प्रस्ताव का पूरा पाठ :–

Hkkरतीय जनता पार्टी देश में व्याप्त कृषि संकट पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करती है। कृषि भारत में सिर्फ एक आर्थिक गतिविधि भर नहीं है बल्कि देश की दो तिहाई आबादी अपने रोजगार के लिए इसी पर निर्भर है। यू.पी.ए. सरकार मौजूदा कृषि संकट से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए त्वरित एवं पर्याप्त उपाय करने में विफल रही है और इसके कारण हमारे किसानों की आजीविका खतरे में पड़ गई है।

भारत को एक ऐसे आर्थिक मॉडल की आवश्यकता है जो संतुलित विकास पर केन्द्रित हो तथा वह देश में लोगों की आमदनी में गहरा असंतुलन न पैदा करती हो। हमें किसान केन्द्रित आर्थिक मॉडल की आवश्यकता है क्योंकि विकास के पश्चिमी मॉडल हमारे देश के लिए उपयुक्त नहीं है। पश्चिमी मॉडल तो अब उन यूरोपीय और उत्तरी अमरिकी देशों में भी अपना प्रभाव खो रहे हैं, जहां इस विकास मॉडल का जन्म हुआ।

यदि भारत को इक्कीसवीं शताब्दी की महान आर्थिक शक्ति बनाना है तो हमें विकास का एक नया मॉडल देना पड़ेगा।

कृषि से दूर होते किसान

भारत के किसान त्रस्त हैं क्योंकि कृषि अलाभकारी हो गई है। उनकी स्थिति मार्मिक है क्योंकि कृषि के सभी जरूरी अवयवों के लागत मूल्य में भारी वृद्धि हुई है जबकि उसके अनुपात में न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि नहीं हुई। इसके कारण उन्हें या तो कृषि छोड़ने पर या फिर अपनी भूमि 'परती' छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है।

नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानि NSSO के आंकड़े कहते है कि यदि किसानों को विकल्प उपलब्ध हो तो 42 फीसदी किसान कृषि छोड़ देना चाहते है। किसानों के मन में कृषि से पलायन की बढ़ती धारणा का सबसे भयावह रूप हमें विदर्भ (महाराष्ट्र), बुन्देलखण्ड (उत्तर प्रदेश) रायॅलसीमा–कोनसीमा (आन्ध्र प्रदेश) के इलाकों में देखने को

मिलता है।

संभवतः स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब रॉयलसीमा–कोनसीमा क्षेत्र के धान उत्पादक किसानों ने कृषि संकट से परेशान होकर पिछले साल खरीफ के मौसम में धान की फसल न उगाने का सामूहिक निर्णय लिया। इसके कारण इस इलाके के 1.25 लाख एकड़ भूमि परती पड़ी रह गई।

इन धान उत्पादक किसानों की सहायता करने में यू. पी.ए. सरकार नाकाम रही।

कर्ज एवं सूखे की समस्या

लाखों किसान कर्ज के भारी बोझ तले दबे हुए है। कई बार हताश किसान इस बोझ से छुटकारा पाने के लिए अपनी जीवनलीला समाप्त करने पर विवश हो जाता है। किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं की लगातार बढ़ती घटनाओं के प्रति यू.पी.ए. सरकार का जो असंवेदनशील रवैया रहा है वह हमें ब्रिटिश सम्राज्य की क्रूरता का स्मरण कराता है।

प्रधानमंत्री और सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष ने महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके का दौरा किया जहां हजारों किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। उन्हें राहत प्रदान करने के लिए 2006 में कई सौ करोड़ का एक आर्थिक सहायता पैकेज दिया गया मगर छह सालों में किसानों को उनकी समस्याओं से निजात नहीं मिली है। कांग्रेस पार्टी पिछले कई सालों से किसानों से खोखले वायदे करती आ रही है।

विदर्भ अब एक और संकट, भयंकर सूखे के संकट का सामना कर रहा है। सूखे की समस्या बुन्देलखण्ड, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश समते देश के कुछ अन्य भागों में भी बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड इलाके में तो लोगों को पीने का पानी भी नसीब नहीं हो रहा है।

भाजपा केन्द्र सरकार से मांग करती है कि किसानों एवं ग्रामीणों द्वारा जिस गंभीर सूखे के संकट का सामना किया जा रहा है उसकी तरफ से आंख न मूंदे। सरकार को चाहिए कि देश के सभी सूख ग्रस्त इलाकों के लिए एक राष्ट्रीय सूख आपदा राहत पैकेज की घोषणा करे। भाजपा किसानों को ऋणमुक्त करने के लिए पूर्णतः कटिबद्ध है।

कृषि ऋण आबंटन प्रक्रिया की असलियत

यद्यपि यू.पी.ए. सरकार ने किसानों को मिलने वाले कृषि ऋण के बजट आबंटन को 2011–12 में दिए गए 4.75 लाख करोड़ रुपए में बढ़ा कर 2012–13 में 5.75 लाख करोड़ करने का प्रस्ताव अपने नए बजट में रखा है लेकिन जैसा कि आंकड़े बताते है कि इस का उपयुक्त लाभ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड और पश्चिम बंगाल के किसानों को नहीं मिलेगा जहां बड़ी संख्या में गरीब और छोटे किसान रहते है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार कृषि ऋणों का एक बहुत बड़ा हिस्सा दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे महानगरों में रहने वाले 'किसानों' को वितरित किया जाता है जहां कृषि के लिए कोई भूमि शायद ही बची हो।

अकेले इन दोनों शहरों में ही 2009–10 में 32,400 करोड़ रूपए का कृषि ऋण वितरित किया गया है जितना कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखण्ड के किसानों को मिलाकर भी नहीं दिया गया। इन चारों प्रदेशों में कुल मिलाकर 31,000 करोड़ रूपए का कृषि ऋण 2009–10 में वितरित किया गया।

कृषि ऋण को बांटने की मौजूदा नीति की तत्काल समीक्षा की जानी चाहिए और इस बात की जांच होनी चाहिए कि कहीं कृषि ऋण के लिए मिलने वाले धन का उपयोग रीयल इस्टेट सेक्टर में तो नहीं किया गया है।

भाजपा सरकार से यह भी मांग करती है कि सस्ते कृषि ऋण की सुविधा सिर्फ कृषि संबंधी अवयवों जैसे खाद एवं बीज तक ही सीमित नहीं रखी जाए बल्कि कृषि उपकरण की खरीद के लिए भी यह सस्ता कृषि ऋण मिलना चाहिए। इससे किसानों को कृषि में श्रम लागत को घटाने का अवसर मिलेगा जो मौजूदा समय में कुल लागत का करीब 25 फीसदी हिस्सा है।

सरकार का सब्सिडी विरोधी रवैया

हाल ही में केन्द्र सरकार ने अपनी Nutrient based Subsidy (NBS) नीति के तहत नाइट्रोजन एवं पोटेशियम उर्वरकों पर दी जाने वाली सब्सिडी घटाने का निर्णय लिया है। उर्वरक मंत्रालय ने नाइट्रोजन एवं पोटेशियम पर 24 रूपए प्रति किलो तथा फास्फेट पर 21.8 रूपए प्रति किलो की सब्सिडी घटाने का निर्णय लिया है।

इस निर्णय से सरकार अगले वित्त वर्ष में सब्सिडी बिल करीब बीस फीसदी तक घटाने की उम्मीद कर रही है। 'P&K' फर्टिलाइजर्स के लिए प्रतिवर्ष करीब 52,000 करोड़ रूपए की सब्सिडी दी जा रही है और कुल सब्सिडी बिल करीब 90,000 करोड़ का है।

सरकार को कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली सब्सिडी को वित्तीय अनुशासन के नाम पर समाप्त नहीं करना चाहिए। भाजपा यह मांग करती है कि उर्वरक सब्सिडी सीधे किसानों को मिलनी चाहिए और इस संबंध में सरकार को 'फॉलोअप एक्शन' लेना चाहिए। जैविक कृषि के लिए भी सब्सिडी का प्रावधान होना चाहिए।

पिछले आठ वर्षों में सरकार ने उद्योग एवं व्यापार जगत को करीब 22 लाख करोड़ की टैक्स राहत जिसमें आयकर

छूट का लाभ भी शामिल है जैसी सुविधाएं प्रदान की हैं। कर अवमुक्त करने से होने वाली राजस्व हानि हर साल बजट के 'Revenue forgone' मद में अंकित की जाती है। लेकिन कृषि के लिए ऐसी कोई छूट या सहायता सरकार ने नही दी।

घटती कृषि भूमि

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत की कुल कृषि योग्य भूमि 2003–04 में 183.19 मिलियन हेक्टेयर से घटकर 2009–10 में 182.39 मिलियन हेक्टेयर ही रह गया है। भले ही यह आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला न हो मगर इसमें यह साफ पता चलता है कि भारत में कृषि भूमि लगातार घट रही है।

अमरीका जैसे देश भी अपने यहां कृषि भूमि के सरंक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए 'फार्म बिल 2008' के अन्तर्गत 750 मिलियन अमरीकी डॉलर का आबंटन कर रहे है। भारत में भी कृषि भूमि संरक्षण के लिए गंभीर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है और केन्द्र सरकार को इस दिशा में जरूरी कदम उठाने चाहिए।

किसान हितैषी भूमि अधिग्रहण कानून जरुरी

किसानों के विस्थापन और उनकी उपजाऊ जमीनों के जबरिया अधिग्रहण के कारण सरकार ने किसानों के बीच काफी आक्रोश पैदा किया है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यसमिति ग्रामीण विकास के लिए गठित संसदीय समिति के इस अनुमोदन का स्वागत करती है कि विकास के नाम पर किसी भी उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए।

वर्ष 1894 से चले आ रहे भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन किए जाने की मांग काफी समय से उठ रही है। नए संशोधित भूमि अधिग्रहण बिल में सरकार ने अभी भी 'लोकहित' को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करते हुए मुनाफे से प्रेरित निजी कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए गुंजाइश बनाए रखा है। ऐसा लगता है कि यू.पी.ए. सरकार ने सिंगूर एवं नंदीग्राम (पश्चिम बंगाल), टप्पल एवं भट्टा परसौल (उत्तर प्रदेश) में हुए किसान आंदोलनों से कोई सबक नही सीखा है।

भाजपा नए भूमि अधिग्रहण विधेयक में मौजूद सभी किसान विरोधी प्रावधानों पर संसद में बहस के दौरान पूरा प्रतिवाद और प्रतिरोध करेगी।

भूख के खिलाफ 'शून्य सहनशीलता'

यू.पी.ए. सरकार ने भूख की समस्या से निपटने के लिए जितने भी कार्यक्रम बनाए हैं उनकी एक लंबी सूची है। हर साल इन सभी योजनाओं के लिए सरकार बजट आबंटन में भी वृद्धि करती है, इसके बावजूद लाखों गरीब लोग भारत में भूख एवं कुपोषण के शिकार है। भारत 88 देशों के 'Global Hunger Index' में 67वें पायदान पर है। करीब 5000 बच्चे प्रतिवर्ष कुपोषण के कारण काल कवलित हो जाते है।

भाजपा एक ऐसी नीति का समर्थन करती है जहां भूख की समस्या के प्रति 'शून्य सहनशीलता' यानि 'Zero Tolerance Towards Hunger' का भाव हो। भारत का मौजूदा खाद्यान्न उत्पादन भारत की सवा अरब आबादी का पेट भरने के लिए हमारी आवश्यकताओं से अधिक है। यदि यू.पी.ए. सरकार के पास खाद्यान्न प्रबंधन की कोई कारगर नीति हो। तो हम इस 'सरप्लस' का उपयोग निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित करने में कर सकते हैं। भारत में भूख को मौजूदा समस्या मुख्यतः सरकार की गलत नीतियों एवं कुप्रबंधन का दुष्परिणाम है। भाजपा एक भूख–मुक्त भारत के लिए कटिबद्ध है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार

सरकार को मौजूदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावकारी बनाने के लिए इसमें सुधार लाने के लिए प्रयास करना होगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्धारित खाद्यान्न काफी बड़ी मात्रा में खुले बाजार में पहुंच जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाला खाद्यान्न भ्रष्टाचार के कारण नेपाल, बर्मा, बांग्लादेश यहां तक कि सिंगापुर तक पहुंच जाता है।

भाजपा इस बात में गौरव की अनुभूति करती है कि भाजपा शासित छत्तीसगढ़ राज्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आदर्श मॉडल इस देश की जनता के सामने रखा है। देश के अन्य राज्यों में भी इस मॉडल का अनुसरण होना चाहिए। भाजपा सरकार से यह मांग करती है कि मौजूदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन किया जाना चाहिए।

खाद्यान्न खरीद एवं भण्डारण की गलत नीति

यू.पी.ए. सरकार को अपनी गलत खरीद एवं भण्डारण नीति में सुधार करने की महती आवश्यकता है। हमारे देश की मौजूदा भण्डारण क्षमता पूरी तरह जीर्ण शीर्ण है जिसके कारण खरीद में पांच फीसदी की वृद्धि भी भण्डार गृहों को दबाव की स्थिति में ला देता है।

इस साल गेहूं उत्पादक किसानों को कई राज्यों में अपनी फसल काफी कम दामों में बेचनी पड़ी क्योंकि सरकार अपनी गेहूं खरीद के लक्ष्य को ही नहीं पूरा कर पाई। यहां तक कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को बारदाना (गेहूं का बोरा) तक उपलब्ध कराने का काम भी सरकार के लिए एक बोझ बन गया।

भारत का मौजूदा खाद्यान्न भंडारण का आधारभूत ढांचा बेहद जर्जर और अत्यधिक केन्द्रीकृत है। आज किसान बम्पर फसलों का उत्पादन कर रहा है मगर उसकी मेहनत बेकार जा रही है। भाजपा, सरकार से यह मांग करती है कि वह एक 'नेशनल फूड स्टोरेज ग्रिड' का निर्माण करे जो ग्रामीण भण्डार गृहों, FCI के भंडारों को जोड़कर बनाई जाए जिसकी मॉनिटरिंग केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा की जाए।

जीन संवर्धित फसलों पर रोक लगे

केन्द्र सरकार देश में जीन संवर्धित फसलों यानि Genetically Modified (G.M) Crops पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की घोषणा करे क्योंकि जी.एम. फसलों से उत्पादकता नहीं बढ़ने वाली। इन फसलों से होने वाले 'Cross Pollination' के कारण किसानों के स्वामित्व वाले परम्परागत बीजों की किस्मों के प्रदूषित होने का भी खतरा पैदा हो गया है।

मौजूदा Intellectual Property Rights (IPR) यानि बौद्धिक सम्पदा अधिकार के तहत बीज की बहुराष्ट्रीय कम्पनियां 'रॉयल्टी' के नाम पर भारत की बीज सुरक्षा को नष्ट कर देना चाहती है। बीज सुरक्षा देश की खाद्य सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यदि बीज पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का नियंत्रण पैदा हो गया तो हमारे देश की खाद्य सुरक्षा पर भी संकट आ जाएगा।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहन

विश्व की तमाम बड़ी कम्पनियों के लिए भारत एक विशाल उपभोक्ता बाजार है और इसका भरपूर फायदा उनके द्वारा उठाया जा रहा है। लेकिन भारत के किसान एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्यरत उद्यमी इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि सरकार उन्हें बाजार से जोड़ नहीं रही है।

भारत में फलों एवं सब्जियों में मात्र 2.2 प्रतिशत, दूध में 35 फीसदी, मांस में 21 फीसदी, पोल्ट्री उद्योग में 0.6 फीसदी क्षमता ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए तैयार हो पाई है। इस कारण 'वैल्यू एडीशन' केवल 20 फीसदी के स्तर पर है जो अन्तर्राष्ट्रीय मानकों से काफी नीचे है। हर साल करीब 13 अरब डॉलर मूल्य के खाद्य पदार्थ भारत में खाद्य प्रसंस्करण की सुविधाओं के अभाव में खराब हो जाते है।

यूपीए खाद्य प्रसंस्करण के लिए भंडारण उपयुक्त तंत्र बनाने में पूर्णतः विफल सिद्ध हुयी हैं। खाद्य प्रसंस्करण के लिए यू.पी.ए. सरकार द्वारा दी जाने वाली नाममात्र की धनराशि यह दर्शाती है कि सरकार किसानों को 'Value Addition' एवं 'Market Access' के माध्यम से पूरा लाभ नहीं होने देना चाहती। भाजपा सरकार से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बजट आबंटन में वृद्धि की मांग करती हे।

सिंचाई एवं नदी जोड़ो परियोजना

नदी जोड़ो परियोजना श्री अटलजी के नेतृत्व वाली एन. डी.ए. सरकार का 'Dream Project' था जिसे बाद में यू.पी.ए. सरकार ने समाप्त कर दिया। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में केन्द्र सरकार को यह निर्देश दिया है कि लगभग 30 नदियों को जोड़ने का सिलसिला प्रारंभ हो ताकि सूखे से जूझ रहे इलाकों तक पानी पहुंच सके।

भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करती है क्योंकि इससे इस देश के उन लाखों किसानों के मन में आशा की किरण जगी है जो देश में सिंचाई सुविधाओं के अभाव में संकट का सामना कर रहे हैं।

सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए भूजल स्तर में सुधार लाने के लिए नीतियां बनाई जाए। पानी की बचत के लिए किसानों को 'ड्रिप' और 'स्प्रिंकल' सिस्टम से सिंचाई करने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। इसके लिए उन्हें सब्सिडी मिले।

भारत जैसे देश मं जहां सिंचाई सुविधाएं अपर्याप्त है वहां 'वाटरशेड प्रबंधन' की भूमिका बढ़ जाती है। गुजरात और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकारों ने बारिश का पानी रोकने के लिए हजारों–लाखों 'चेक डैम्स' बनाने का शानदार काम किया है।

मिट्टी की गुणवत्ता और जैविक कृषि

अधिकांश राज्यों में कृषि में हो रहे रासायनिक पदार्थो के प्रयोग के कारण मिट्टी में जैविक तत्वों की कमी चिंताजनक स्तर तक पहुंच गई है। पंजाब जैसे राज्य में मिट्टी में जैविक तत्वों की मौजूदगी लगभग शून्य (0.1–0.2 प्रतिशत) के स्तर तक पहुंच गई है।

रासायनिक पदार्थों के अतिशय प्रयोग के कारण पर्यावरण और खाद्य श्रृंखला पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यह सब इसलिए हुआ है क्योंकि हमने उन समुन्नत प्रजातियों की फसलों को बढ़ावा दिया है जिन्हें रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों की काफी आवश्यकता थी। इसलिए मिट्टी की गुणवत्ता यदि सुधारना है तो हमें हरी खाद और कम्पोस्ट खाद की तरफ ध्यान देना होगा।

सरकार को कृषि के प्रति नजरिए में बदलाव लाने की जरूरत है और जैविक कृषि को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए क्योंकि यही कृषि भारत के लिए दीर्घकाल तक चल सकती है। गुजरात और कर्नाटक जैसे राज्य जैविक कृषि को बढ़ावा देने में अग्रणी हैं लेकिन इसे राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया जाना

चाहिए।

जैविक कृषि की संभावनाओं के विकास के लिए वृहद शोध कार्य किए जाने चाहिए ताकि भारत पारम्परिक कृषि ज्ञान की क्षमता को निखारा जा सके।

विश्व में जैविक कृषि उपज की मांग लगातार बढ़ रही है मगर सही दिशा के अभाव में भारत के किसान इस अवसर का लाभ नही उठा पा रहे है। नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड (National Horticulture Board) एवं Agricultural Processed Food Products Export Development Authority यानि 'एपिडा' (APEDA) को चाहिए जैविक कृषि उपज के प्रमाणन की प्रक्रिया की जिम्मेदारी एवं खर्च वहन करें क्योंकि आम किसान इस प्रक्रिया में लगने वाले भारी खर्च को वहन करने में असमर्थ है। सरकार को जैविक कृषि/जैविक उर्वरकों के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त सब्सिडी उपलब्ध करानी चाहिए।

कृषि अनुसंधान

कृषि अनुसंधान का मौजूदा मॉडल अपने रास्ते से भटक गया है। कृषि अनुसंधान विभिन्न 'Agro Climatic Zone' में होने वाले 'National Resource Management' पर आधारित होना चाहिए। कृषि अनुसंधान संबंधी दस्तावेज एवं साहित्य स्थानीय भाषाओं में भी तैयार किए जाने चाहिए।

विश्व व्यापार संगठन का प्रभाव

भारतीय कृषि को विश्व व्यापार संगठन के दायरे में घसीटा गया है और सरकार ने जब किसानों को उनके उत्पादों के लिए विदेशी बाजार उपलब्ध कराए तब तक विकसित देशों ने अपने देश में कृषि क्षेत्र को भारी सहायता देकर अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों को बुरी तरह बिगाड़ दिया था।

भारत के किसान विकसित देशों के किसानों का मुकाबला नहीं कर सकते। यूरोपीय संघ के देशों एवं अमरीका ने अपने बाजारों को भांति–भांति के tariff barriers लगा कर सुरक्षित कर रखा है। अपने Farm Bill 2008 के माध्यम से अमरीका ने किसानों को सीधे भुगतान की जाने वाली राशि में 10 फीसदी की वृद्धि की है।

कृषि क्षेत्र में NDA का योगदान

जब भाजपा नेतृत्व वाली NDA सरकार सत्ता में थी तो हमने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए थे। हमने कृषि कार्यों के लिए ब्याज दरों में भारी कटौती की, कृषि आय बीमा योजना लागू की, किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए, किसानों को लाभकारी मूल्य दिया और कृषि में दीर्घकालीन विकास सुनिश्चित हो इसके लिए पहली बार एक राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया।

दुर्भाग्य से एन.डी.ए. सरकार द्वारा किए गए बहुत सारे अच्छे काम पर यू.पी.ए. सरकार ने पानी फेर दिया है। यू.पी.ए. सरकार ने कृषि आय बीमा योजना समाप्त कर दी जो भारतीय कृषि के उत्थान की दिशा में क्रांतिकारी योजना थी। स्वामीनाथन आयोग ने दिसम्बर 2004 से अक्टूबर 2006 के बीच अपनी चारों रिपोर्ट सौंप दी मगर आज तक यू.पी.ए. सरकार उसे लागू नहीं कर पाई है।

भाजपा शासित राज्यों ने अपने सीमित संसाधनों के बावजूद कृषि के पुनरुत्थान और किसानों की सुरक्षा के प्रति काफी प्रतिबद्धता दिखाई है। हमने लगभग सभी भाजपा शासित राज्यों में कृषि कार्यों के लिए बेहद कम ब्याज दर सुनिश्चित की है जो एक फीसदी के कम स्तर तक जाती है। यहां गुजरात जैसे प्रदेश ने कृषि क्षेत्र में शानदार प्रगति की है।

भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी अपनी इस मुम्बई बैठक में निम्नलिखित सुझावों का अनुमोदन करती है जिनसे कृषि किसानों के लिए लाभकारी उद्यम सिद्ध होगी।

1. कृषि और सिंचाई जैसे क्षेत्रों के लिए केंद्र द्वारा अधिक आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जानी चाहिए।
2. कृषि कार्यों के लिए दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज महज एक फीसदी हो।
3. सरकार सभी किसानों के लिए अनिवार्य रूप से एक बैंक अकाऊंट खोले जिसमें सभी तरह का भुगतान जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य, क्षतिपूर्ति, सब्सिडी भुगतान तथा अन्य कोई भुगतान सीधे नगद रूप में प्रदान किया जा सके।
4. सरकार नदी जोड़ो परियोजना पर तुरंत कार्य प्रारंभ करे।
5. भारत की देसी गायों की प्रजाति में सुधार के लिए शोध किया जाना चाहिए। देसी गायों की प्रतिरोधक क्षमता बेहतर है और वे हमारी जलवायु के अनुरूप ढल जाती है। इससे जैविक कृषि को भी बढ़ावा मिलेगा।
6. एक ऐसी Regulating Authority भी गठित हो जो बीजों के दाम एवं वितरण पर नियंत्रण कर सके।
7. कृषि उपकरण जैसे ट्रैक्टर, मशीनरी, सिंचाई उपकरण जैसे ड्रिप स्प्रिंकल इत्यादि, उर्वरक, बीज को नाना प्रकार के करों से मुक्त किया जाना चाहिए। इन पर मिलने वाली सब्सिडी भी बढ़ाई जानी चाहिए।
8. प्रत्येक जिला मुख्यालय पर मृदा परीक्षण, खाद, बीज और कीटनाशकों की जांच के लिए आधुनिक प्रयोगशालाएं होनी चाहिए। इससे किसानों को मदद मिलेगी जो नकली खाद, पानी बीज की समस्या का सामना कर रहे है।

9. सरकार को हर जिले में एक 'सीड बैंक' बनाना चाहिए जहां स्वदेशी बीजों का संवर्धन एवं वितरण हो सके।
10. कृषि उत्पादों के आयात को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए।
11. एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिसमें किसान की मासिक आय सुनिश्चित हो जिसकी गणना 'न्यूनतम समर्थन' मूल्य के आधार पर हो। किसानों के लिए आय बीमा योजना (एफ.आय.आय.एस.) लागू की जानी चाहिए।
12. मौजूदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करके उसे मजबूत बनाया जाना चाहिए। इस संदर्भ में छत्तीसगढ़ की सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अनुकरण होना चाहिए।
13. ग्रामीण इलाकों में कृषि आधारित लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और सरकार द्वारा उन्हें प्रोत्साहन, संरक्षण और आर्थिक तथा तकनीकी सहायता प्राप्त हो।
14. प्रत्येक किसान को 'Soil Health Card' जारी किया जाए और मृदा परीक्षण के लिए मौजूदा प्रयोगशालाओं का तुरन्त आधुनिकीकरण प्रारंभ हो।
15. एक जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए जिसमें किसानों को अपने खेत के जैविक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सहयोग मिल सके।
16. सरकार राष्ट्रीय कृषक आयोग की रिपोर्ट को अविलम्ब लागू करे।
17. न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करते समय स्वामीनाथन आयोग द्वारा सुझाए गए फार्मूले का ध्यान रखा जाए तथा समर्थन मूल्य की घोषणा फसल की बुवाई के पहले हो।
18. सरकार अपनी Nutrient based Subsidy (NBS) नीति वापिस ले ताकि किसानों को फास्फेट एवं पोटाश उर्वरकों की बढ़ती कीमतों से सुरक्षित किया जा सके।
19. कृषि को 'मनरेगा' के साथ जोड़ा जाए।
20. पशुधन एवं मत्स्य विभाग के लिए भी उपयुक्त आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जानी चाहिए।
21. खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय खाद्य ग्रिड स्थापित किया जाना चाहिए। ■

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

पृष्ठ 15 का शेष...

- केन्द्र सरकार को देश में विशेष रूप से तीन राज्यों– महाराष्ट्र, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश– में सूखे की स्थिति का जायजा लेने के लिये तुरन्त मंत्रियों का एक ग्रुप गठित करना चाहिये और स्थिति से निपटने के लिये नीति सम्बन्धी उचित निर्णय तेजी से लेने चाहिये।
- इन राज्यों में से प्रत्येक को 1500 करोड़ रूपये की अन्तरिम सहायता और 500 करोड़ की सहायता उत्तर–प्रदेश–मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए यथाशीघ्र प्रदान की जानी चाहिये। इसके अलावा केन्द्र को इन राज्यों में से प्रत्येक के लिये 5 लाख मीटरिक टन अनाज निःशुल्क रिलीज करना चाहिये ताकि वह अनाज प्रभावित लोगों को बांटा जा सके। ऐसा बिना किसी कठिनाई के किया जा सकता है क्योंकि केन्द्र के पास सरप्लस स्टाक उपलब्ध है और उसके भण्डारण के लिये जगह भी नहीं है।
- सीमेंट चैक बांधों, मिट्टी वाले बांधों और माइक्रो जल संचयन ढांचों पर कार्य आरंभ करने के लिये प्रभावित राज्यों को विशेष पैकेज दिया जाना चाहिये जिन्हें इस ग्रीष्म ऋतु में ही पूरा किया जाये। इससे जल स्तर को गिरने से रोकने और पीने के पानी की कमी को दूर करने में सहायता मिलेगी और आगामी खरीफ फसल के लिये सुरक्षित सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
- चारा बैंक स्थापित किये जाये और निःशुल्क रेल परिवहन सुविधा देकर युद्ध स्तर पर पड़ौसी राज्यों से इन राज्यों को चारा उपलब्ध कराया जाये ताकि पशुधन में हो रही कमी को रोका जा सके।
- छत पर जल संचयन (रूफ टॉप वाटर हारवेस्टिंग) अनिवार्य बनाया जाना चाहिये। बोर कुओं, ट्यूबवेलों का कायाकल्प अनिवार्य बनाया जाय और फार्म तालाबों के निर्माण पर भी जोर दिया जाना चाहिये।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाया जाना चाहिये।
- फसल संबंधी ऋणों का ब्याज माफ करके पुनः निर्धारण किया जाना चाहिये।
- बर्बाद हो गई फसल के लिये प्रति एकड़ 6000 रुपए की इनपुट सब्सिडी तुरन्त रिलीज की जानी चाहिये।
- मनरेगा योजना को सूखाग्रस्त राज्यों के कृषक मजदूरों के लिए भी लागू किया जाना चाहिए। ■
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

यूपीए ने देश को गर्त में धकेला

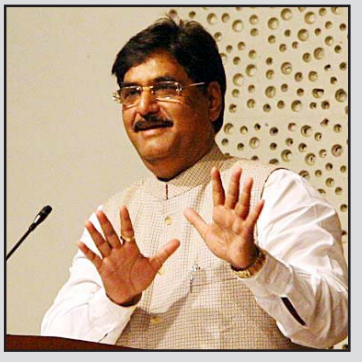

भाजपा कार्यकारिणी बैठक के दूसरे दिन 25 मई को सर्वसम्मति से राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे लोकसभा में पार्टी के उपनेता श्री गोपीनाथ मुंडे ने प्रस्तुत किया और इसका समर्थन भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री श्री रविशंकर प्रसाद एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने किया। इस प्रस्ताव पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली ने समापन वक्तव्य दिया। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि अगर आम आदमी इस सरकार में पीड़ित और ठगा हुआ महसूस कर रहा है, अगर किसान आत्महत्या कर रहे हैं, अगर औद्योगिक उत्पादन में भयंकर गिरावट है, अगर बेरोजगारी बढ़ रही है और अगर भयंकर भ्रष्टाचार रोज नए–नए आयामों में प्रकट हो रहा है और जब देश में यू.पी.ए. के कुशासन के कारण भंयकर निराशा और असंतोष है तब भाजपा अपना नैतिक दायित्व समझती है कि वह देश की पीड़ित जनता की आवाज को गंभीरता से उठाए। प्रस्तुत है प्रस्ताव का पूरा पाठः–

यूपीए सरकार ने 2009 के लोकसभा चुनाव में दोबारा सत्ता में आने के बाद अपने तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए जिस आम आदमी का हितैषी होने का प्रचार करती है वही आम आदमी इस सरकार के कुशासन का सबसे बड़ा शिकार बना है। कुशासन, भ्रष्टाचार और उदासीनता के कारण गरीब आदमी का दुख, उपेक्षा और पीड़ा सभी हदों को पार कर चुकी है। सच्चाई तो यह है कि भारत के विकास की कहानी के सभी दावे संदेह और अविश्वास के घेरे में आ गए हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार की नीतिगत विफलताओं और उसके खराब शासन के कारण दुनिया भर में भारत की साख गिरी है। घिसट–घिसटकर चलना यूपीए–2 की विशेषता बन गई है। उम्मीद का माहौल खत्म हो गया है और भारत के एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरने के सपने पर अब न केवल तटस्थ पर्यवेक्षक बल्कि ऐसे लोग भी गंभीरता से सवाल उठा रहे हैं जो इस सरकार के विशेष सलाहकार हैं। यह सब इस महान देश की असाधारण सामर्थन और इसकी जनता की असीम क्षमता के बावजूद हो रहा है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने उम्मीद, उत्साह, भागीदारी, वास्तविक विकास, मंहगाई के ठोस प्रबंधन और सामान्य सद्भावना और आशा की महान विरासत छोड़ी थी जिसकी वजह से भारत को नई ऊंचाइयां छूने को मिली और भारत एक महत्वपूर्ण देश के रूप में उभरकर सामने आया था। आज इसकी जगह अंधकार और निराशा का माहौल है। इस सभी का कारण ढूंढना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। एक सफल सरकार चलाने और किसी भी कार्यक्रम को लागू करने के लिए तीन चीजें आवश्यक हैं। पहला नेतृत्व ऐसा होना चाहिए जो फैसले लेने और उन्हें लागू करने की क्षमता रखता हो। दूसरा सरकार की विश्वसनीयता है और तीसरी महत्वपूर्ण बात है सरकार की साख। प्रधानमंत्री को स्वाभाविक रूप से देश और सरकार का नेता होना चाहिए और नीतिगत मामलों में उनकी ही बात मानी जानी चाहिए। डा. मनमोहन सिंह दोहरी कसौटी पर खरा उतरने में एकदम ही नाकाम रहे हैं। देश में न केवल दोहरा नेतृत्व है बल्कि 7 रेसकोर्स रोड और 10 जनपथ की दूरी बढ़ती जा रही है। नीतिगत पहलों पर भी वे एकमत नहीं हैं। सरकार मंत्रियों और गठबंधन के सहयोगियों के बीच कोई तालमेल नहीं है। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि वे चीजों को दुरूस्त रखें। हांलाकि हर दिन इस बात की पुष्टि कराई जाती है कि प्रधानमंत्री अपने पद पर आसीन हैं लेकिन उन्हें अधिकार प्राप्त नहीं है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वह एक सीईओ की तरह काम कर रहे हैं, जिसे एक कम्पनी के बोर्ड से निर्देश मिलते हैं जिसके चौयरमैन के पास सारे अधिकार हैं लेकिन वास्तव में कोई जवाबदेही नहीं है।

नीतिगत विफलता और मुद्रास्फीति

नीतिगत विफलता और भ्रष्टाचार के परिणाम चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। निवेश कम हुआ है, औद्योगिक माहौल

बिल्कुल अनुकूल नहीं है और भ्रष्टाचार ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर है, अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग अनुकूल नहीं हैं और रूपया गिरा है, डॉलर के मुकाबले रूपये का 22 प्रतिशत अवमूल्यमन हो चुका है। डॉलर मंहगा होने के कारण अब छात्रों, पर्यटकों और सरकार को ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। वृद्धि और विकास के लिए जरूरी कई नीतिगत पहल अधर में लटके पड़ी हैं क्योंकि सरकार और यूपीए के भीतर न केवल स्पष्टता और आम सहमति का अभाव है बल्कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ मंत्री भी अलग–अलग भाषा बोल रहे हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री के पास राजनैतिक अधिकार होना जरूरी है जो दुर्भाग्य से उपलब्ध नहीं है। निष्क्रियता और भ्रष्टाचार के लिए गठबंधन की राजनीति की मजबूरी का बहाना नहीं बनाया जा सकता। विपक्ष के साथ सहमति बनाने का काम एकतरफा नहीं हो सकता जबकि वरिष्ठ मंत्री राज्यों के साथ, विपक्ष से निपटते समय अहंकार वाली बयानबाजी करते हैं और विपक्ष द्वारा शासित राज्यों के लिए परेशानियां खड़ी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते।

मुद्रास्फीति खासतौर से खाद्यान्नों की कीमतें एक बार फिर बढ़ने के कारण न केवल गरीब आदमी का जीवन दूभर हो गया है बल्कि मध्यम वर्ग के लिए भी काफी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। ऐसा लगता है कि सरकार ने हाथ खड़े कर दिये हैं। उसके पास खाद्यान्नों की बढ़ती कीमतों की समस्या से निपटने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं है जिसके कारण अर्थव्यवस्था लम्बे अरसे से चौपट पड़ी है। यह एक विडम्बना ही है कि भारतीय किसानों की कड़ी मेहनत के कारण अनाज के रिकॉर्ड उत्पादन के बावजूद, अनाज खुले में सड़ रहा है क्योंकि भंडारण की पर्याप्त सुविधा नहीं है और अत्यधिक गरीब और हाशिये पर चले गए लोगों को खाना नसीब नहीं हो रहा है। सरकार के पास इस गंभीर मुद्दे से निपटने के लिए कोई रोडमैप नहीं है और यह स्थिति बार–बार पैदा हो रही है। अर्थव्यवस्था का प्रबंधन खासतौर से खाद्य अर्थव्यवस्था घोर असंतोषजनक है जबकि पिछले 8 वर्ष से एक जाने–माने अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री हैं। पेट्रोल की कीमत पर एक दिन में 7 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी आज तक कभी नही हुअी। अपनी तीसरी वर्षगांठ पर यूपीए के द्वारा देश के गरीब जनता को दिया गया एक क्रूर उपहार हैं।

भ्रष्टाचार यूपीए सरकार का अभिन्न अंग

भाजपा ने कुछ समय पहले अपनी पिछली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकों में स्पैक्ट्रम मत व्यक्त किया था कि आजादी के बाद सबसे भ्रष्ट केन्द्र सरकार का नेतृत्व डा. मनमोहन सिंह कर रहे हैं। इस अवधारणा में बदलाव की कोई वजह नहीं दिखाई देती। भ्रष्टाचार करना और भ्रष्टाचार करने वाले को संरक्षण देना उनके शासन की विशेषता बन गई है। यहां तक कि गठबंधन के सहयोगियों और कांग्रेस पार्टी से जुड़े लोगों की भ्रष्टाचार में लिप्तता को लेकर अलग–अलग मानदंड बना दिए गए हैं। मौजूदा गृह मंत्री पी. चिदम्बरम जब वित्त मंत्री थे तो उस समय 2जी घोटाला हुआ जो आजादी के बाद राजनीतिक भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मामला है, इसमें उनकी खुद की भूमिका का काफी संदेह के घेरे में है और इसकी निष्पक्ष जांच करने की आवश्यकता है। फिर भी वह प्रधानमंत्री के निर्विवाद विश्वासपात्र बने हुए हैं। जिस तरह से अत्यधिक संदेहपूर्ण परिस्थितियों में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) ने होल्डिंग कंपनियों के जरिये एयरसेल मैक्सिस सौदे को मंजूरी दी उसे लेकर अनेक गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस सौदे में श्री चिदम्बंरम के परिवार के सदस्य कथित रूप से शामिल हैं। इस सौदे की सीबीआई जांच कर रही है जिसमें तत्कालीन दूरसंचार मंत्री श्री मारन की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

आदर्श घोटाले में महाराष्ट्र के अनेक कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के नाम आए हैं और हैरानी की बात यह है कि उनमें से कई केन्द्र सरकार में मंत्री बने हुए हैं। राष्ट्रमंडल खेल घोटाले में दिल्ली की मुख्य मंत्री शीला दीक्षित को लगातार संरक्षण दिया जा रहा है जबकि इस मामले की जांच के लिए खुद प्रधानमंत्री द्वारा गठित शुंगलू समिति की रिपोर्ट में उनकी भूमिका के खिलाफ गंभीर टिप्पणियां की गई हैं। हाल ही में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में एंट्रिक्स–देवास सौदे को शासन व्यवस्था की विफलता का अनूठा उदाहरण करार दिया गया। रिपोर्ट में यह टिप्पणी की गई है कि इसरो के पूर्व प्रमुख और अन्य अधिकारियों ने सरकार के हितों की अनदेखी की और निजी कंपनी देवास को फायदा पहुंचाया। अंतरिक्ष मंत्रालय सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन है, इसके बावजूद ऐसा हुआ। कैग ने एयर इंडिया के विमानों की खरीद में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार पाया। उर्वरक सब्सिडी के मामले में भी भारी भ्रष्टाचार हुआ है। हर रोज एक नया घोटाला या घपला सामने आ रहा है। कैग ने अपनी रिपोर्ट मे कोयला ब्लॉक के आवंटन मे भी भयंकर अनियमितताओं को उजागर किया है। कैग ने दिल्ली हवाई अड्डे के निजीकरण में भी भयंकर अनियमितताओं को पाया है।

काले धन का पता लगाने के लिए प्रभावी और अर्थपूर्ण समयबद्ध कार्यक्रम चलाने तथा विदेशों में काला धन जमा करने वालों के नाम जनता के सामने लाने के लिए सरकार में राजनैतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। सरकार जानती है

कि अगर यह नाम उजागर हो गए तो उसकी फजीहत होगी। काले धन पर संसद मे सरकार द्वारा जारी वक्तव्य सिर्फ दिखावा है। इसमे कोई दिशा और स्पष्ट नीति का अभाव है जिससे विदेशी बैंकों में जमा काले धन को लाया जा सकें। रिपोर्ट से इस चौकाने वाले तथ्य का पता चलता है कि 2006 से 2010 के बीच स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा भारतीयों के पैसे में 60% की गिरावट हुई। रु 23,273 करोड़ रु. से कम होकर यह राशि 2010 में 9295 रुपये रह रह गई। हालांकि इस पूरी राशि का आकलन भी काफी कम है। लेकिन इससे यह ज्ञात होता है कि 2008 के बाद भाजपा द्वारा इस विषय को गंभीरता से उठाने के बाद वहां से ये पैसा निकाला गया। भाजपा महसूस करती है कि सशस्त्र बलों के लिए होने वाली खरीद के अनेक सौदों में भ्रष्टाचार का होना गंभीर चिंता का विषय है। सेना के लिए टाट्रा ट्रक की आपूर्ति ने भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर अनेक चिंताजनक सवाल खड़े कर दिये हैं।

कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के प्रति गंभीर नहीं है। प्रधानमंत्री और यूपीए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा भ्रष्टाचार रोकने की गई सभी घोषणाएं खोखली और हास्यास्पद लगती हैं। अगर भाजपा द्वारा खासतौर से काफी आक्रामक अभियान नहीं चलाया गया होता और जागरूक मीडिया और अदालत की निगरानी नहीं होती तो किसी भी घोटाले में कोई कार्रवाई यू.पी.ए. सरकार द्वारा नहीं होती। कांग्रेस का भ्रष्टाचार करने वालों के दुष्कर्म को छिपाने के लिए अपने अधिकारों का दुरूपयोग करने की निर्लज्जता दिखाने का रिकॉर्ड रहा है।

हाल के चुनाव परिणाम

राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पिछली बैठक के बाद अनेक राज्यों में चुनाव हुए। पंजाब में अकाली दल, भाजपा गठबंधन भारी बहुमत से विजयी रहा। पिछले 40 वर्ष में ऐसी पहली सरकार थी जो सत्ता पर रहते हुए दोबारा चुनी गई। जाहिर है कि लोगों ने अकाली–भाजपा सरकार द्वारा किये गए अच्छे कार्यों पर भरोसा किया। इन दोनों दलों का सम्बन्ध 40 वर्ष से ज्यादा पुराना है। गोवा में भाजपा की भारी जीत काबिले तारीफ है। ईसाई मतदाताओं की बड़ी संख्या सहित औसत मतदाताओं के बहुमत को कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार के कुशासन से छुटकारा पाने के लिए भाजपा एकमात्र उम्मीद के रूप में दिखाई दी। बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों ने भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर इस दुष्प्रचार को खत्म कर दिया कि भाजपा अल्पसंख्यक विरोधी है। वे भाजपा इस सिद्धांत की सराहना करते हैं कि सभी को न्याय मिले और किसी का तुष्टिकरण नहीं हो। उत्तराखंड राज्य में एक सीट कम रहने के कारण हम अपनी सरकार नहीं बना पाए। हम नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा की गई कड़ी मेहनत की सराहना करते हैं लेकिन इससे सबक लेने की जरूरत है। उत्तरप्रदेश के चुनाव परिणाम संतोषजनक नहीं रहे। कार्यकर्ताओं और समर्थकों के जबरदस्त चुनाव प्रचार और कड़ी मेहनत के बावजूद, हम वहां लोगों की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर सके। हमें गंभीरता से आत्म विश्लेषण करने, सुधार करने और पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को प्रेरित और उत्साहित करने की जरूरत है। भाजपा को उत्तर प्रदेश में पहले लोगों का विश्वास और समर्थन मिल चुका है। हमें इसे दोबारा हासिल करने की जरूरत है। मणिपुर में पार्टी की कड़ी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल सका फिर भी हमें वहां अपना जनाधार बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करने होंगे। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को न केवल भारी नुकसान हुआ बल्कि मतदाताओं ने मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरू के नगर निगम चुनावों में उसे बुरी तरह से सबक सिखाया। इससे यूपीए सरकार के कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता के गुस्से का पता चलता है।

संघीय ढांचे का लगातार उल्लंघन

बार–बार विरोध व्यक्त करने के बावजूद यूपीए ने राज्य सरकारों के अधिकार को कम करने के लिए संघीय ढांचे के सिद्धांतों के साथ छेड़छाड़ जारी रखी है। यूपीए के सहयोगी दलों सहित विपक्ष के विरोध के बावजूद यह लगातार जारी है। हाल में केन्द्र सरकार का एकतरफा और मनमर्जी करने का उदाहरण देखने को मिला। उसने जिस तरीके से राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केन्द्र (एनसीटीसी), रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) कानून में सुरक्षा संबंधी अधिकार को लेकर संशोधन किये उससे केन्द्र और राज्यों के बीच में अविश्वास और संदेह बढ़ा है। देश की आंतरिक सुरक्षा को मनमाने ढंग से नहीं देखा जा सकता। राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रबंधन और संघीय ढांचे के सिद्धांतों के सम्मान को लेकर कोई मतभेद नहीं है। इस सम्बंध में राज्य सरकारों की बराबर की भागीदारी और जिम्मेदारी है। केन्द्रीय सहायता और संसाधनों के आवंटन में भेदभाव राज्यों की बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए कोयला खदानों के आवंटन और राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित अनेक विधेयकों को मंजूरी नहीं दिये जाने जैसे भेदभाव के अनेक उदाहरण गंभीर चिंता का कारण हैं। ऐसा निष्कर्ष निकालना सही होगा कि संघीय ढांचे के सिद्धांतों का सम्मान कांग्रेस के डीएनए का हिस्सा नहीं है।

आतंकवाद और नक्सल हिंसा का खतरा

भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यह बैठक मुंबई में

हो रही है और हमारे लिए यह जरूरी है कि हम 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के मुख्य षड्यंत्रकारियों और इसकी योजना बनाने वालों को अभी तक सजा नहीं दिलाने जाने पर गंभीर रोष प्रगट करें। वे पाकिस्तान में सुरक्षित घूम रहे हैं क्योंकि उन्हें पाकिस्तान के शासकों और सेना का संरक्षण हासिल है। इस बारे में भारत सरकार पाकिस्तान को विस्तृत जानकारी के साथ दर्जनों दस्तावेज दे चुकी है लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। भाजपा का दृढ़ मत है कि पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाना तब तक संभव नहीं है जब तक वह अपनी जमीन से भारत के खिलाफ होने वाली आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ कड़ी और निर्णायक कार्रवाई नहीं करता। भारत को आतंकवाद के साथ लड़ाई में पूरी तरह से सतर्क रहने और कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है। आतंकवाद से निपटने के लिए किसी तरह की कोताही और समझौता नहीं होना चाहिए क्योंकि यह सुरक्षा और एकता का मामला नहीं है बल्कि इससे देश की संप्रभुता जुड़ी हुई है।

माओवादी हिंसा ने गंभीर चिंता और चुनौती खड़ी कर दी है। पूरे देश को इस समस्या से पूरी तरह से सतर्क रहने की जरूरत है और इस चुनौती से निपटने के लिए केन्द्र एंव राज्य सरकारों के बीच पूरा तालमेल होना चाहिए। गरीबों की समस्याओं का हल ढूंढा जाना चाहिए लेकिन हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि माओवादियों का मूल उद्देश्य हिंसा के जरिये संसदीय लोकतंत्र का तख्ता पलटना और राजनीतिक ताकत हासिल करना है। यही वजह है कि वे जबरन निर्दोष लोगों का अपहरण और हत्या करते हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। हम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की इस घोषणा की सराहना करते हैं कि अगर मुख्यमंत्री का भी अपहरण हो जाता है तो उनकी नाजायज मांगों के आगे नहीं झुका जाना चाहिए।

पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के हालात और शरणार्थियों की स्थिति

पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों खासतौर से हिन्दुओं की स्थिति बहुत दयनीय है। वहां पर हिन्दू लड़कियों का अपहरण करने के बाद जबरन धर्मांतरण करने और उनकी इच्छा के विरूद्ध विवाह कराने की घटनाएं अकसर सुनने को मिलती हैं। पुलिस ही नहीं बल्कि न्यायपालिका भी कई मामलों में उन्हें न्याय नहीं दिला पाती। पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों में अनेक हिन्दू पेशेवर और व्यवसायियों की हत्या। की जा चुकी है। हिन्दू ही नहीं बल्कि ईसाई भी दहशत में जी रहे हैं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के पूजा स्थलों पर भी हमला हो रहा है। मानवाधिकार संगठनों ने अपनी अनेक रिपोर्टों में इस दुर्दशा की विस्तार से जानकारी दी है। हमारा भारत सरकार से आग्रह और मांग है कि वह पाकिस्तान के साथ दृढ़ता से सभी कूटनीतिक उपाय करे और पाकिस्तान में इन अल्पसंख्कों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इससे जुड़े अन्य उपाय भी करे।

पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर से आये हिन्दू शरणार्थियों की स्थिति गंभीर चिंता का विषय है। उन्हें धार्मिक कारणों और अपनी आस्था के कारण जबरन वहां से भागना पड़ा क्योंकि उनके नागरिक और सांस्कृतिक अधिकारों का हनन हो रहा था तथा एक सम्मानजनक जीवन जीने की स्थितियां भी नहीं थी। भारत सरकार को उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए सभी उपाय करने चाहिए जिससे वे भारत में इज्जत और आत्मसम्मान के साथ रह सकें। उन्हें जबरन उनकी मातृभूमि से खदेड़ा गया है और वहां का शासन उनके बुनियादी मानवाधिकारों की अवहेलना कर रहा है। उन्हें शरणार्थियों और मानवाधिकार के उल्लंघन संबंधित अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार सन्मान से जीवन यापन का अवसर मिलना चाहिए।

संस्था का पतन

यूपीए सरकार एक के बाद एक विवादों में घिरती चली गई और इस कारण संस्थाओं का पतन होने लगा है। उसने न केवल सिविल सोसाइटी को नाराज किया है जो भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदारी तय करने की मांग कर रही है बल्कि कैग और चुनाव आयोग के साथ भी उसका तकरार बढ़ा है। वे अपनी स्वायत्तता में हस्तक्षेप किये जाने की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। हमें अपनी सेना के साहस और शौर्य पर गर्व है जो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। वे हमारे संविधान और राजनैतिक स्वरूप के अनुसार राजनैतिक नेतृत्व के नियंत्रण मे काम करते हैं। हाल में सरकार और सेना के सम्बन्धों में तनाव के अनेक उदाहरण सामने आए जिनसे मजबूत शासन व्यवस्थाओं के जरिये बचा जा सकता था। भाजपा भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए पर्याप्त अधिकारों के साथ एक प्रभावी लोकपाल के लिए प्रतिबद्ध है और इस सम्बन्ध में कोई देरी नहीं की जानी चाहिए।

निष्कर्ष

यूपीए ने देश के शासन को गर्त में धकेल दिया है। भ्रष्टाचार, अनिर्णय, मंहगाई और असुरक्षा का भाव पैदा होने के कारण जनता की तकलीफें बढ़ गई हैं। वे भाजपा की ओर देख रहे हैं। हमारा कर्त्तव्य है कि हम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरें और देश की जनता को आश्वस्त करें कि भाजपा ही देश को विकास के रास्ते पर ले जा सकती है।

यू.पी.ए. सरकार के तीन वर्ष पूरे होने के कार्यक्रम मे

शेष पृष्ठ 29 पर

'नॉन पेपर' है काले धन पर लगाया गया 'श्वेत पत्र'

भाजपा कार्यकारिणी बैठक में सर्वसम्मति से आर्थिक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री प्रकाश जावडेकर ने प्रस्तुत किया और इसका अनुमोदन पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री पीयूष गोयल ने किया। प्रस्ताव पर समापन वक्तव्य भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने दिया। इस प्रस्ताव में देश की आर्थिक स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा गया है कि कांग्रेस ने एक बार फिर देश को गंभीर आर्थिक संकट में धकेल दिया है जो 1991 के डरावने दिनों की याद दिलाते हैं। आगे कहा गया है कि भाजपा भारत के लोगों की दृढ़ इच्छाशक्ति और विश्वास को आधार मानती हैं और संप्रग सरकार की विनाश करने वाली आर्थिक नीतियों के विरोध में आंदोलन करने का आह्वान करती है। प्रस्तुत है प्रस्ताव का पूरा पाठ :–

Hkkरतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी भारतीय अर्थव्यवस्था के ह्रास होती हुई अवस्था पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करती है। कांग्रेस ने एक बार फिर राष्ट्र को संकट में डाल दिया है। जिन्होंने इतिहास से सबक नहीं लिया वह इसे दोहराने के लिए दंडित किये जाते हैं। देश को गंभीर आर्थिक संकट में धकेल दिया गया है जो 1991 के डरावने दिनों की याद दिलाते हैं। देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट, सरकार के पूर्णतः लकवाग्रस्त होने के स्थिति को प्रदर्शित करता है, जो कांग्रेस नीत यूपीए सरकार की महत्वपूर्ण विशेषता है। कुछ दिनों पहले, यूपीए ने देश के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया था, जिसमें कड़वे सच की अनदेखी की गई और खोखले दावों के द्वारा अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति को छिपाया गया।

मंदी, भ्रष्टाचार और कुप्रशासन भारत को यूपीए सरकार की देन है। यूपीए सरकार की दयनीय कार्यपद्धति के कारण देश भारी कीमत चुका रहा है और इस स्थिति को बदलने में कई वर्षों का समय लगेगा। यह ध्यान देने योग्य बात है कि राजग ने भारत की मंदी की अर्थव्यवस्था को तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर दिया था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने एक फलती–फूलती अर्थव्यवस्था को संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करके एनडीए के ठीक विपरीत उपलब्धि हासिल की हैं।

अर्थव्यवस्था की स्थिति निराशाजनक बनी हुई है। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 7 प्रतिशत के नीचे गोता लगा रहा है जबकि उपभोक्ता मुद्रास्फीति लगातार द्विअंकीय बनी हुई है। निर्यात 6 प्रतिशत से कम हो गया हैं। फारेक्स रिजर्व तेजी से घट रहा है और 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर से नीचे चला गया है। राजकोषीय घाटा निर्धारित लक्ष्य 4.6 प्रतिशत से काफी आगे निकल गया है और जीडीपी के 6 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया है। 3.4 प्रतिशत का राजस्व घाटे के साथ चालू खाते का घाटा 4.3 प्रतिशत होना, भारतीय अर्थव्यवस्था की निराशाजनक स्थिति का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत कर रहा है। इससे भी ज्यादा चिंता का विषय है कि चालू खाते घाटे का 70 प्रतिशत कम अवधि के डेब्टस् द्वारा वित घोषित है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक पिछले वर्ष के +8.5 प्रतिशत के मुकाबले –3.5 प्रतिशत तक गिर गया है। जीडीपी का 20 प्रतिशत बाह्य डेब्टस् के रुप में है। 2009 में केपिटल आउटफ्लो 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर था जो 2011 में बढ़कर 44 बिलियन अमेरिकन डॉलर हो गया है। ब्याज की दरें उंची है और तरलता की स्थिति बिगड़ी हुयी है। पूंजीगत निवेश भी कम होता जा रहा है जो भविष्य की डरावनी स्थिति की पूर्वचेतावनी दे रहा है। भारत के तीन शीर्ष बॅकोकी रेटिंग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घटा दी गयी हैं। प्रत्येक प्रतिमान हमारी चिंता को दृढ कर रहा है कि पिछले 8 वर्षों से विशेषतौर पर 2009 से यूपीए के द्वारा किये गये सम्पूर्ण कुप्रबंधन के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था घोर संकट में फंस चुकी है।

रुपया अनिर्वचनीय रुप से एक वर्ष में अमेरिकी डॉलर के विरुद्ध 25 प्रतिशत गिर गया है और आज 56 रुपयों की मनोवैज्ञानिक सीमा को पार कर चुका है और यह गिरावट निरंतर जारी है। इसके परिणास्वरुप आयात महंगा होगा, कच्चा तेल और उर्वरक का आयात बिल बढ़ेगा और कारपोरेट भारत की बैलेन्स शीट बुरी तरह प्रभावित होगी। यहां तक कि भारत के युवाओं को विदेश में जाकर अध्ययन करने की लालसा भी महंगी शिक्षा लागत के कारण चकनाचूर होगी। सरकार की जिम्मेवारी हैं कि वह राष्ट्र को यह स्पष्टीकरण दे कि आखिर क्यों रुपयों का मूल्य लगातार गिर रहा है, जबकि दूसरी मुद्राओं में ऐसी कोई गिरावट नहीं दिखाई देती।

भारतीय जनता पार्टी पेट्रोल के दामों में 7.50 रुपयों की हैरान करनेवाली, स्वीकार न करने योग्य बढ़ोत्तरी की निंदा करती हैं। पहले से ही प्रत्येक भारतीय के मासिक बजट में भारी दबाव है। इस बढ़ोत्तरी से यह दबाव और बढ़ेगा। सरकार को बढ़ोतरी के बजाय पेट्रोलियम उत्पादों पर करारोपण को कम करना चाहिए था, जिसके माध्यम से सरकार 150,000 करोड़ रुपये वार्षिक एकत्र कर रही है। भारतीय उपभोक्ताओं को एशिया में सबसे ज्यादा दाम चुकाने के लिए बाध्य किया जा रहा है। भाजपा यह मांग करती है कि पेट्रोल के दामों को सरकार तत्काल प्रभाव से कम करे तथा राष्ट्रव्यापी और मजबूत लोकतांत्रिक आंदोलन के लिए सरकार को स्वयं तैयार रहना चाहिए। राजग ने 31 मई भारत बंद की घोषणा की है।

सबसे ज्यादा चिंता की बात है, यह आर्थिक सूचकांक गंभीर आर्थिक प्रवृत्ति की ओर संकेत कर रहे है जिसे वापस पटरी पर लाने में कई वर्ष का समय लगेगा। प्रथमतया भारत की अर्थव्यवस्था पुराने केपिटलिस्टा द्वारा हथिया ली गयी है जो अनैतिक साधनों द्वारा अपना लाभ बढ़ाना चाहते है। पिछले कुछ वर्षों में उजागर हुए विभिन्न घोटाले, 2जी स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम, आदर्श घोटाला, टाट्रा–वेक्ट्रा, कोल आवंटन घोटाले यह दर्शाते है कि सरकार उन लोगों को ठेका, लाइसेंस और अनुमति दे रही है जो सरकार को रिश्वत देने के इच्छुक है। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करके, सरकार नैतिक व्यापार को घटायेगी, निवेश कम होगा और केपिटल का प्रभाव अवरुद्ध होगा, वास्तव में भी यही हो रहा है। निवेशकों और व्यापारियों का विश्वास का पुनःप्राप्त करना बहुत ही मुश्किल होगा। दूसरा– हम तेजी से डेब्टट्रेप में जकड़ते जा रहे हैं। डेब्ट–जीडीपी का अनुपात 67 प्रतिशत पर चल रहा है और मुद्रास्फीति के कारण यह और ज्यादा ही होगा।

आंतरिक देनदारी कर कुल सार्वजनिक देनदारी का 82 प्रतिशत होना, यह प्रदर्शित करता है कि निजी क्षेत्र के लिए उधार मिलना मुश्किल हो रहा है। कम अवधि के लिए बाह्य डेब्ट, कुल बाह्य डेब्ट का 40 प्रतिशत हो चुका है जो भुगतान संतुलन को संतुलित कर रहा है। डेब्ट को बेहतर तरीके से प्रबंध करने की आवश्यकता है जिसके लिए वित्तीय विवेकशीलता आवश्यक है।

अन्ततः सरकार ने बढ़ी संख्या में महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों की योजना शुरू की है, उन योजनाओं को आगे चलाने के लिए धन की व्यवस्था करना कठिन काम होगा। इन योजनाओं में मनरेगा, खाद्य–सुरक्षा, अधिकार आरएसबीवाय और अन्य योजनाएं है। स्पष्टतया, आशा यह थी कि उंची वृद्धि दर इन योजनाओं के लिए वित्त की व्यवस्था कर देगी। अब जब अर्थव्यवस्था लड़खडा रही हैं, सरकार का वित्तीय घाटा ऐतिहासिक रुप से उंचे स्तर पर है और टैक्स–टू–जीडीपी की दर कम है, अर्थव्यवस्था को सुव्यवस्थित करने का कोई उपाय नहीं बचा है।

असफल बजट

ऐसे मौके पर, सरकार से विकास आधारित बजट को प्रस्तुत करने की आशा थी। परंतु इसके बजाय सरकार ने इस अवसर को खो दिया। विकास की भावना से दूर, सरकार ने एक्साइज और अन्य करों को बढ़ाकर उच्च स्तर का अप्रत्यक्ष कर लागू किया। सरकार ने सेवा कर बढ़ाया और लगभग सभी सेवाओं को इस दायरे में लाने का प्रयास किया है। जीएएआर और आभूषणों पर लगाये गये करों को सभी वर्गों द्वारा विरोध करने पर हटाना पड़ा है। अप्रत्याशित और नाटकीय ढंग से पेट्रोल के दामों में भी कई बढ़ोतरी भी यह दर्शाती है कि सरकार के द्वारा एक के बाद एक गलती की जा रही हैं। केवल हाथ भर लगाने की नीति की तरह वित्तमंत्री अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के साधनों की घोषणा करती है।

1991 की वापसी

वर्तमान आर्थिक स्थिति 1991 के आर्थिक संकट के प्रारंभ के दिनों से मेल खाता हैं, 1991 का आर्थिक संकट कांग्रेस सरकार के चार दशकों की अक्षम नीति द्वारा खड़ा किया गया था। वित्तीय और चालू खाते का अत्यधिक घाटा, रुपये का लगातार कमजोर होना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में वृद्धि, घरेलू बाजार में ब्याज की उंची दरें, अपनी ही आंखों के सामने संपूर्ण प्रभूत्व संपन्न रेटिंग का गिरना, बड़े भुगतान दायित्व, कम अवधि के उच्च बाह्य ऋण, धीमा विकास है और उच्च मुद्रा स्थिति से कोई तुलनात्मक आधार नहीं है। तेजी से विदेशी निवेशकों का बहिर्प्रवाह जारी है और कुछ ही समय में आयात का फॉरेक्स कवर 14 माह से 7 माह की निचले स्तर पर आ चुकी है।

इस निराशाजनक इस स्थिति के लिए सरकार की

लकवाग्रस्त नीतियां जिम्मेवार है और सरकार को भ्रष्टाचार की नीतिगत फड़फड़ाहट के कारण निवेशकों का विश्वास चकनाचूर हो गया हैं। इस देश के लोगों ने इस सरकार पर से अपना विश्वास खो दिया है। यह सरकार जितनी जल्द जाएगी इस देश के लिए इतना ही अच्छा होगा। सरकार के सहयोगियों को जनता विरोधी नीतियों के कारण आनेवाले परिणाम को भुगतना ही पड़ेगा। केवल कुछ वैयक्तिक या अन्य लोगों के निर्णयों से सरकार का स्वयं को अलग करने से काम नहीं चलनेवाला है।

एनडीए शासन काल के दौरान बेहतरीन विकास

जब 1998 में एनडीए सत्ता में आया था तब विकास दर 5 प्रतिशत से भी कम थी और आधारभूत संरचना की स्थिति भी बुरी तरह बिगड़ी हुई थी। भाजपा के नेतृत्व में एनडीए ने वित्तीय सुदृढीकरण पर ध्यान केंद्रित किया और बीमा, बैंकिंग, दूरसंचार, उर्जा और जमीन अधिकरण इत्यादि विषयों पर महत्वपूर्ण सुधार किये थे। एनडीए सरकार ने आधारभूत संरचना के विकास के लिए सड़क, बंदरगाह, एयरपोर्ट, रेलवे और सिंचाई के विकास पर ध्यान दिया। इस सरकार ने विनिवेश कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चलाया और मॅक्रोइकॉनॉमिक प्रतिमानों का विकास किया था। एनडीए का शासन काल पूर्वी एशिया के संकट, पोखरण विस्फोट के बाद लगाए गये आर्थिक प्रतिबंधों, जबरदस्त सुखा की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की तीन बार बढ़ोतरी जैसे अनेक वैश्विक और घरेलू कठिनाइयों के बावजूद श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में आर्थिक क्षेत्र मे अधिशेष के युग के रुप में रहा था। एनडीए ने मंद अर्थव्यवस्था को तेजी से विकास की ओर जानेवाली अर्थव्यवस्था में परिवर्तित किया था।

यूपीए की अक्षमता

संप्रग सरकार स्वयं को छोड़कर लगातार सभी लोगों पर आरोप मढ़ रही हैं और अपनी अक्षमता को कभी स्वीकार नहीं करती। कभी बाहरी कारणों, कभी राज्य सरकारों, कभी सरकार के अपने सहयोगियों पर आरोप लगाती है परंतु अधिकांश समय विपक्षी पार्टियों पर दोषारोपण करती है। उनके अनुसार सरकार के अलावा सभी लोग उसके द्वारा किये गये कुशासन के लिए जिम्मेवार हैं। ऐसे बहाने बनाकर राष्ट्र को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। संप्रग को 2004 में राजग से एक मजबूत और जीवंत अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी, एनडीए ने 8.4 प्रतिशत की विकास दर के साथ 4 प्रतिशत से भी कम मुद्रास्फीति और न्यूनतम ब्याज दर 6 वर्षों के अंतर्गत फॉरेक्स रिजर्व को 29 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 113 बिलियन अमेरिकी डॉलर करना और अंतिम 3 वर्षों में चालू खातों के अंतर्गत अधिशेष उपलब्ध कराया था।

दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस स्थिति को गतिमान बनाए रखने के बजाय यूपीए सरकार ने 2004 की एनडीए सरकार द्वारा दी गयी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। संप्रग सरकार ने 8 वर्षों में उपभोगव्यय 300 प्रतिशत बढ़ा दिया और 2009 के चुनाव के मौके पर किये गैरउत्पादक व्यय में मुद्रास्फिति के कुप्रबंधन को और बढावा दिया। वर्तमान समय में अनिर्णय की स्थिति ने आधारभूत संरचना को बुरी तरह प्रभावित किया है। खनन, तेल, गैस, उर्जा और अन्य उद्योग इस अनिर्णय की स्थिति के शिकार हुए है। यहा तक की उर्जा क्षेत्र के तैयार प्रोजेक्ट भी कोयला उपलब्ध नहीं होने के कारण बंद हो गये हैं। कई निवेशी प्रोजेक्ट ठप्प हो गये है और भारतीय व्यापारी भी विदेशों में निवेश कर रहे हैं। सिंचाई में अपर्याप्त निवेश के कारण कृषि विकास की हानि हुई है। यूपीए सरकार के मंत्री स्वयं ही रेल्वे, एअर इंडिया, एमटीएनएल, बीएसएनएल को आइ.सी.यू. में भर्ती रोगी के रुप में वर्णित कर रहे है। नेतृत्वहीनता का और कुशासन के परिणामस्वरुप सुधार रुक गये है।

भ्रष्टाचार और कालाधन

संप्रग सरकार ने घोटालों की सरकार, घोटालों के द्वारा सरकार और घोटालों के लिए सरकार की विशेषता हासिल की है। 2जी स्पैक्ट्रम, कॉमनवैल्थ, कोयला घोटाला, देवास अंतरिक्ष घोटाला, आदर्श सोसाइटी, डिफेंस भूमि, टाट्रा घोटाला, सिविल एयरक्राफ्ट खरीदी, इन सभी घोटालों में से प्रत्येक घोटाले में घोटालों के आकार और अधिक बढ़ा है और निर्लज्जता की सारी हदें पार की हैं। कैग जैसी संवैधानिक संस्था इतने घोटालों को उजागर करने में कभी भी इतनी व्यस्त नहीं रही जितनी की आज है। वस्तुस्थिति की अवहेलना करना, सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले (व्हिसलब्लोअर) पर आक्रमण करना, प्रयुक्त धन की मात्रा और अनुत्पाद को हास्यास्पद बताना और जब चाहे तब कैग और पीएसी जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर आक्रमण करना और अपने सहयोगियों पर आरोप मढ़ देने से संप्रग की प्रतिक्रिया को आसानी से समझा जा सकता है–जब संदेह से गिरे सहयोगी मंत्रियों को बचाने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने की बात आती है तो संप्रग अपनी सारी हदें पार कर लेता है। संप्रग केवल तभी न्यूनतम कार्रवाई करता हैं जब न्यायालय उसे ऐसा करने के लिए बाध्य करता है।

क्वात्रोची के खातों की डिफ्रीजिंग और बोफोर्स मामले को दबाया जाना संप्रग की भ्रष्टाचार के प्रति मानसिकता को स्पष्ट तौर पर परिलक्षित करता है। संप्रग की भ्रष्टाचार के खिलाफ 'जीरो टॉलरेन्स' की घिसीपिटी नीति पूरी तरह

खोखली दिखायी पड़ती है। संप्रग के इन अपराधों को राष्ट्र ना ही भूल सकता है और ना ही उसे कभी क्षमा करेगा।

सरकार का काले धन पर लाया गया तथाकथित श्वेत पत्र या तो इस मुद्दे पर 'नॉन पेपर' या ब्लेन्क पेपर है। यह ना तो कालेधन की मात्रा के बारे में कुछ बताता है और ना ही टैक्स हेवन्स में जमा किये धन–राशि को वापस लाने के बारे में कोई बात करता है और ना देश के भीतर काले धन को रोकने के प्रयास के बारे में कुछ बताता है। बड़बोलापन किसी भी नीतिगत मामले का विकल्प नहीं होता। अब जब कालेधन के मुद्दे पर ठोस कार्रवाई करने और इस मामले में सरकार का जबाब पाने के लिए राष्ट्र प्रतीक्षा कर रहा है तब संप्रग इस मुद्दे को दिशा से भटकाने और लटकाने के लिए श्वेतपत्र जैसे हथियार का उपयोग कर रहा है।

आम आदमी के साथ विश्वासघात

आम आदमी बढ़ती हुई महंगाई से त्रस्त है, ऐसा प्रतीत होता है कि मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकार के पास कोई विचार है ही नहीं। आपूर्ति पर ध्यान देने के बजाय सरकार ब्याज की दरें बढ़कर तरलता को घटाने का कार्य कर रही हैं, जिसका प्रभाव है कि, महंगाई और अधिक बढ़ रही है। आम आदमी के साथ सबसे बढ़ा विश्वासघात तब किया गया जब सरकार ने निर्लज्जतापूर्वक ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की सीमा 22 रुपये और शहरी क्षेत्रों में गरीबी की सीमा 29 रुपये प्रतिदिन निर्धारित करने की चेष्टा की।

जब भारतीय युवा रोजगार पाने की राह देख रहे हैं तब संप्रग द्वारा उन्हें रोजगार–हीन विकास दिया जा रहा है।

आगे की ओर

प्रतिदिन 20 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करने, उर्जा के लिए कोयला आपूर्ति करने, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर समय रहते उनके प्रमुख नियुक्त करने से सरकार को किसी ने नहीं रोका है। यह सरकार ही है जो स्वयं हर मोर्चे पर विफल हुई हैं। भाजपा भारत के लोगों की दृढ़ इच्छाशक्ति और विश्वास को आधार मानती है और संप्रग सरकार की विनाशकारी आर्थिक नीतियों के विरोध में आंदोलन करने का आह्वान करती है। अवसर प्राप्त होने पर, भाजपा यह आश्वासन देती है कि, वह रोजगार के अवसरों को बढ़ाने, लोगों को मुक्त करने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण, कौशल विकास, स्वास्थ्य सुविधा, आधारभूत संरचना के विकास के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करा कर, भारत के बृहद घरेलू मांग के अंतर्गत उपलब्ध अवसर का समुचित उपयोग करते हुए घरेलू और विदेशी दोनों ही स्तर पर निजी निवेश बढ़ा कर, सरकार के खर्च को प्रभावी ढंग से उत्पादक कार्यों के लिए निर्देश देकर और वित्तीय विवेकशीलता से प्रभावी कदम उठाकर एक बार फिर भारतीय अर्थव्यवस्था को विकास के पथ पर वापस लायेगी।■

पृष्ठ 25 का शेष...

श्रीमती सोनिया गाँधी ने सराकार के संबंध मे विपक्ष विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी की टिप्पणियों को गैर–जिम्मेवार और आक्रामक बताया है। उनका यह कहना दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इसकी भर्त्सना करते है। अगर आम आदमी इस सरकार में पीड़ित और ठगा हुआ महसूस कर रहा है, अगर किसान आत्महत्या कर रहे हैं, अगर औद्योगिक उत्पादन में भयंकर गिरावट है, अगर बेरोजगारी बढ़ रही है और अगर भयंकर भ्रष्टाचार रोज नए–नए आयामों में प्रकट हो रहा है और जब देश में यू.पी.ए. के कुशासन के कारण भंयकर निराशा और असंतोष है तब भाजपा अपना नैतिक दायित्व समझती है कि वह देश की पीड़ित जनता की आवाज को गंभीरता से उठाए। यह कार्य पार्टी पूरी निष्ठा और संकल्प के साथ करती रहेगी।

पेट्रोल मूल्यवृद्धि के विरोध में 31 मई को भारत बंद

राजग के कार्यकारी अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी का वक्तव्य

गत 23 मई को यूपीए सरकार ने अकस्मात ही पेट्रोल की कीमतों में सात रूपए से भी अधिक की वृद्धि कर डाली जिससे देश के आम लोगों का जनजीवन कहीं अधिक कष्टमय और दुःखी होकर रह जाएगा, जब कि लोग पहले ही यूपीए सरकार के शासन में निरन्तर बढ़ रही महंगाई से बुरी तरह से त्रस्त हैं। सच तो यह है कि जहां तक मुद्रास्फीति के प्रबंधन, विशेष रूप से खाद्यान्न मुद्रास्फीति की बात है, सरकार पूरी तरह से विचार–शून्य हो गई है। देश के इतिहास में, पेट्रोल की कीमतों में एक ही दिन में इतनी भारी वृद्धि आज तक देखने को नहीं मिली। यूपीए सरकार की पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था के प्रबंधन की स्थिति विशेष रूप से इसके लिए जिम्मेदार है। स्पष्ट है कि आम आदमी ही इसका सबसे बड़ा शिकार होगा। इस प्रकार की मनमानी वृद्धि का विरोध करने के लिए एनडीए ने निर्णय लिया है कि वह 31 मई 2012 को पूरे देश में एक दिन का शांतिपूर्ण 'बन्द' आयोजित करेगी। मैं देश के लोगों से अपील करता हूं कि वे इस शांतिपूर्ण विरोध में अपना पूर्ण सहयोग दें और भाग लें। ■

'यह रिपोर्ट एक शब्दाडम्बरपूर्ण दस्तावेज है'

भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में 'जम्मू और काश्मीर पर वार्ताकारों की रिपोर्ट' पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली ने वक्तव्य प्रस्तुत किया। इसका पूरा पाठ हम यहां प्रकाशित कर रहे हैं :

संसद के अनिश्चितकाल तक स्थगित किए जाने के 36 घण्टे बाद जानबूझ कर जम्मू और काश्मीर पर वार्ताकारों की रिपोर्ट को जारी किया गया है। इसका उद्देश्य रिपोर्ट पर संसदीय जवाबदेही से बचना है।

भाजपा रिपोर्ट पर विस्तार से जांच करने के बाद अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी। परन्तु, पार्टी ने रिपोर्ट की प्रारम्भिक जांच करने पर पाया है कि यह अत्यंत निराशाजनक है। यह रिपोर्ट एक शब्दाडंम्बरपूर्ण दस्तावेज है जिसमें कतिपय आधारभूत वास्तविकताओं को नकारा गया है। इनमें से कुछ तथ्य को रिपोर्ट में अनदेखा कर दिया है:–

(i) पाकिस्तान जम्मू और काश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग स्वीकार नहीं कर पा रहा है और उससे राजनैतिक समस्या के समाधान की कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ती है।

(ii) देश को सीमा–पार और स्थानीय स्तर पर प्रमुख समस्या का सामना करना पड़ता है जिसकी व्यूहरचना या तो पाकिस्तान में रची जाती है या फिर अलगाववादी समूहों की कारस्तानी होती है। इस रिपोर्ट में आतंक–विरोधी उपायों को कम करके दिखाने के सिवा इस समस्या का कोई समाधान नहीं बताया गया है।

(iii) काश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों और सिखों को अत्यधिक आतंकित, पीड़ित और हत्याएं की गई हैं, जिसके कारण उन्हें घाटी छोड़कर भागना पड़ा है जिससे वहां सेक्युलरिज्म और सह–अस्तित्व खतरे में पड़ा रहा है। इस रिपोर्ट में उनके पुनर्वास पर कोई जवाब नहीं दिया गया है।

(iv) भारत की संसद में पारित 1994 के प्रस्ताव में स्वीकृत पाकिस्तान : अधिकृत काश्मीर (पीओके) को भारत के अभिन्न अंग सम्बन्धी भारतीय स्थिति को कमजोर कर दिया गया है। यह रिपोर्ट इस आधार पर तैयार की गई है कि पीओके क्षेत्र का प्रशासन पाकिस्तान करता है और करता रहेगा तथा इसमें पीओके को पीएजे के (पाकिस्तान प्रशासित जम्मू और काश्मीर) के रूप में उल्लेख किया गया है।

(v) रिपोर्ट में इस बात पर भी विचार तक नहीं किया गया कि राज्य में ही विकास, शिक्षा, सरकारी रोजगारों, व्यय एवं निर्वाचित प्रतिनिधियों के मामले में लद्दाख और जम्मू क्षेत्रों के साथ भारी भेदभाव किया जाता है।

(vi) रिपोर्ट में यह बात भी स्वीकार नहीं की गई है कि अनुच्छेद 370 राज्य और देश के शेष भाग के बीच एक मानसिक बाधा बनी हुई है। इससे राज्य और शेष भारत के बीच संवैधानिक कड़ी को कमजोर किया गया है। इसकी बजाय कि इस प्रावधान को समाप्त करने की सिफारिश की जाती, रिपोर्ट में 'अस्थायी' शब्द के स्थान पर 'विशेष' शब्द रख कर इसे स्थायी बना देने की सिफारिश कर डाली है। इससे भविष्य में ''वजीरे–ए–आज़म'' और ''सदर–ए–रियासत'' के पदों की पुनः रचना की उम्मीदें जगाई गई हैं। इसमें सिफारिश की गई है कि 'गवर्नर' (राज्यपाल) की नामजदगी की शुरूआत राज्य विधानसभा से की जाए। इसमें 1952 के पश्चात के कानूनों और जम्मू और काश्मीर में उनके लागू किए जाने की समीक्षा की सिफारिश की गई है। यह एक विनाशकारी कदम होगा क्योंकि ऐसे अनेक कानून हैं जिनको 1953 में डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी के बलिदान और 1975 में इंदिरा–शेख समझौते लागू किया है, जिन पर पुनः विचार करना होगा।

इस रिपोर्ट में ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिन पर भाजपा को आपत्ति है। हमारे संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने एक देश में ''दो विधान; दो प्रधान'' रोकने के लिए अपने जीवन का बलिदान किया था। यह रिपोर्ट उन्हीं बातों का सृजन करना चाहती है जिनका हम सदैव विरोध करते आए हैं। भाजपा ऐसे सभी पहलुओं को पूर्ण रूप से खारिज करती है।■